Indian Council
of World Affairs

रिपब्लिक ऑफ़ कोरिया'ज़ फ़ॉरेन पॉलिसी अप्रोच

फ़्रॉम न्यू सदर्न पॉलिसी टू द इंडो-पेसिफ़िक स्ट्रेटेजी

डॉ. टुन्चिनमांग लैंगेल

ian Council of
World Affairs

रिपब्लिक ऑफ़ कोरिया'ज़ फ़ॉरेन पॉलिसी अप्रोच

फ़्रॉम न्यू सदर्न पॉलिसी टू द इंडो-पेसिफ़िक स्ट्रेटेजी

डॉ. टुन्चिनमांग लैंगेल

Indian Council of World Affairs

भारतीय वैश्विक परिषद् (ICWA) की स्थापना 1943 में सर तेज बहादुर सप्रू और डॉ. एच.एन. कुंजरू के नेतृत्व में प्रख्यात बुद्धिजीवियों के एक समूह द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर एक भारतीय परिप्रेक्ष्य बनाना और विदेश नीति के मुद्दों पर ज्ञान और सोच के भंडार के रूप में कार्य करना था। परिषद आज आंतरिक संकाय के साथ-साथ बाहरी विशेषज्ञों के माध्यम से नीति अनुसंधान आयोजित करती है। यह नियमित रूप से सम्मेलनों, सेमिनारों, गोलमेज़ चर्चाओं, व्याख्यानों सहित बौद्धिक गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित करती है और कई प्रकार के प्रकाशन निकालती है। इसमें एक समृद्ध पुस्तकालय, एक सक्रिय वेबसाइट है और यह इंडिया क्वार्टरली पत्रिका प्रकाशित करती है। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बेहतर समझ को बढ़ावा देने और आपसी सहयोग के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए आईसीडब्ल्यूए ने अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक और अनुसंधान संस्थानों के साथ 50 से अधिक समझौता ज्ञापन किए हैं। परिषद की भारत में अग्रणी अनुसंधान संस्थानों, थिंक टैंक और विश्वविद्यालयों के साथ भी साझेदारी है।

द रिपब्लिक ऑफ़ कोरिया'ज़ फ़ॉरेन पॉलिसी अप्रोच

फ़्रॉम न्यू सदर्न पॉलिसी टू द इंडो-पेसिफ़िक स्ट्रेटेजी

पहली बार प्रकाशित, अगस्त 2023

© Indian Council of World

AffairsISBN: 978-93-83445-83-7

सर्वाधिकार सुरक्षित। कॉपीराइट स्वामी की लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना, इस प्रकाशन का कोई भी भाग किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी रिकॉर्डिंग, या अन्यथा, पुन: प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, पुनर्प्राप्ति प्रणाली में संग्रहीत या पारेषित नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकाशन में तथ्यों और विचारों की जिम्मेदारी विशेष रूप से लेखकों की है और उनकी व्याख्या आवश्यक रूप से इंडियन काउंसिल ऑफ़ वर्ल्ड अफ़ेयर्स, नई दिल्ली के विचारों या नीति को प्रतिबिंबित नहीं करती है।

भारतीय वैश्विक परिषद्
सप्रू हाउस, बाराखम्बा रोड
नई दिल्ली 110001, भारत

टेली: +91-11-2331 7246-49 | फ़ैक्स: +91-11-2332 2710

www.icwa.in

विषय-सूची

सार-संक्षेप		5
परिचय		6
1	कोरिया गणराज्य की विदेश नीति सीमाओं का भू-राजनीतिक विस्तार	11
2	कोरिया गणराज्य की विदेश नीति कूटनीति का संदर्भ: मध्य शक्ति से वैश्विक निर्णायक स्थिति तक	51
3	इंडो-पैसिफ़िक भूरणनीतिक फ्रेमवर्क की ओर कोरिया गणराज्य का संक्रमण: प्रगति या निरंतरता?.....	61
4	कोरिया गणराज्य का इंडो-पैसिफ़िक को गले लगाना: भारत के लिए इसका क्या अर्थ है?.....	64
निष्कर्ष: इंडो-पैसिफ़िक के प्रति कोरिया गणराज्य की विदेश नीति का सारांश.....		76

सार-संक्षेप

यह शोध पत्र विशेष रूप से न्यू सदर्न पॉलिसी (एनएसपी) से इंडो- पैसिफ़िक रणनीति में परिवर्तन के संबंध में कोरिया गणराज्य (कोरिया गणराज्य) की विदेश नीति की लगातार बदलती हुई प्रकृति पर प्रकाश डालता है। इसकी वैश्विक बातचीत, रिश्तों, गठबंधनों और चुनौतियों की जांच करके, यह पत्र इस बात की पड़ताल करता है कि कोरिया गणराज्य के नीतिगत निर्णयों को क्षेत्रीय और वैश्विक अंतर्धाराओं द्वारा कैसे आकार दिया गया है। सुरक्षा प्राथमिकताओं, मध्य शक्ति की स्थिति, "वैश्विक निर्णायक राज्य" बनने की आकांक्षाओं, विकसित होते हितों और वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य के साथ उनके संरेखण का आकलन करते हुए, यह अध्ययन मून जे-इन के राष्ट्रपति पद से लेकर यूं सुक-येओल के कार्यकाल तक कोरिया गणराज्य की विदेश नीति विकल्पों का विश्लेषण प्रदान करता है। एनएसपी के कार्यान्वयन से लेकर इंडो-पैसिफ़िक भू-रणनीतिक ढांचे को अपनाने तक यह शोध विदेशी मामलों पर कोरिया गणराज्य के दृष्टिकोण की जांच प्रस्तुत करता है। अंततः यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे विदेश नीति प्रगतिशील निरंतरता के माध्यम से विकास का प्रदर्शन करते हुए किसी देश की जरूरतों, क्षेत्रीय शक्तियों और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को संभालने की क्षमता को दर्शाती है।

परिचय

विदेश नीति, एक राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रीय हित के अपने लक्ष्यों को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए सिद्धांतों, नीतियों, निर्णयों और अपनाए गए कार्यों की एक सुविचारित कार्यवाही के सघनीकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति का निर्णय आम तौर पर उनकी घरेलू प्राथमिकताओं के साथ-साथ उनके अंतर्राष्ट्रीय विचारों से प्रभावित होता है। अक्सर विचाराधीन तत्व एकजुट होते हैं, जिससे एक सामंजस्यपूर्ण विदेश नीति बनती है जो अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखते हुए अन्य देशों के साथ एक राष्ट्र के संबंधों का मार्गदर्शन करती है। चूंकि ऐसे कई आयाम हैं जो समय के साथ लगातार बदल रहे हैं, यह भी जरूरी है कि किसी देश की विदेश नीति के विकल्प गतिशील प्रभावों के अनुरूप बने रहने के लिए लगातार विकसित होते रहें।

सप्रू हाउस का यह शोध पत्र दक्षिण कोरिया की विदेश नीति के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है, जिसे आधिकारिक तौर पर कोरिया गणराज्य (कोरिया गणराज्य) के रूप में जाना जाता है। शोध मुख्य रूप से पिछले मून जे-इन प्रशासन (2017-2022) की नई दक्षिणी नीति (एनएसपी) पर केंद्रित है और "स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और समृद्ध इंडो-पेसिफ़िक के लिए रणनीति" की दिशा में प्रगति या निरंतरता का अध्ययन करता है।[1] इस इंडो-पैसिफ़िक रणनीति की घोषणा 11 नवंबर 2022 को कंबोडिया में एसोसिएशन ऑफ़ साउथईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) शिखर सम्मेलन के मौके पर राष्ट्रपति यूं सुक-येओल के अधीन वर्तमान प्रशासन द्वारा की गई थी।

1 *Yonhap News Agency*, 2022, "White House hails S. Korea's own Indo-Pacific Strategy, expects stronger security ties", 28 December 2022, https://en.yna.co.kr/view/AEN20221228005052325?section=national/diplomacy

28 दिसंबर 2022 को, यूं सुक-येओल प्रशासन ने इंडो-पैसिफ़िक रणनीति के आधिकारिक सार्वजनिक संस्करण का अनावरण किया।[2] रणनीति दस्तावेज़ इस बात पर ज़ोर देता है कि कैसे कोरिया गणराज्य एक "वैश्विक निर्णायक राज्य" बनने का इच्छुक है, जिसका अर्थ है कि यह "सक्रिय रूप से सहयोग के लिए एजेंडे की तलाश करेगा और क्षेत्रीय और साथ ही वैश्विक स्तर पर चर्चाओं को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाएगा"।[3]

नतीजतन, सियोल ने 2022 में अपने राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाने के लिए वियतनाम के साथ एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी की मांग की है। जापान के साथ वह भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण के माध्यम से सुलह की राह पर है क्योंकि उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु ख़तरे और उसकी पारंपरिक हमलावर क्षमताओं ने इस क्षेत्र को और अधिक अस्थिर कर दिया है। 12 वर्षों के लम्बे अंतराल के बाद, संबंध फिर से मजबूत होने के तुरंत बाद, कोरिया गणराज्य और जापान ने मई 2023 तक दो महीने की अवधि में[4] तीन शिखर सम्मेलन स्तर की बैठकें कीं, 16 मार्च 2023 को पहली शिखर बैठक हुई।[5] 2022 से बढ़ती आवृत्ति के परिणामस्वरूप कोरिया गणराज्य और जापान के बीच अगस्त 2023 में कैंप डेविड में पांचवीं द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन-स्तरीय बैठक हुई।

भारत और कोरिया गणराज्य ने 2023 में अपने राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ भी मनाई और कोरिया गणराज्य द्वारा नई इंडो-पैसिफ़िक रणनीति का अनावरण किया गया, उहोंने अपनी विशेष रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने का भी आह्वान किया है। इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त, कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति यूं सुक-योल ने छह- इसके अतिरिक्त, कोरिया गणराज्य के

---

2 *The Korea Times*, 2022, "Seoul seeks cautious balance in US, China ties via Indo-Pacific Strategy", 29 December 2022, https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2022/12/120_342566.html

3 *Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea*, 2022, "Strategy for a Free, Peaceful, and Prosperous Indo-Pacific Region", 28 December 2022, https://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5676/view.do?seq=322133&page=1

4 *Prime Minister's Office of Japan*, 2023, "Japan-ROK Summit Meeting (Summary)", 21 May 2023, https://japan.kantei.go.jp/101_kishida/diplomatic/202305/21rok.html

5 *Ministry of Foreign Affairs of Japan*, 2023, "Japan-ROK Summit Meeting", 16 March 2023, https://www.mofa.go.jp/a_o/na/kr/page1e_000593.html

राष्ट्रपति यूं सुक-योल ने अप्रैल 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका का छह दिवसीय दौरा पूरा किया, जो कि कोरिया गणराज्य के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष द्वारा 12 वर्षों में पहली बार किया गया था।[6] यह राजकीय यात्रा यूएस-कोरिया गणराज्य गठबंधन की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए थी, और यह बढ़ते भू-राजनीतिक टकराव के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंची थी जैसे कि यूक्रेन-रूस संघर्ष, साथ ही कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ता परमाणु तनाव। यात्रा के दौरान परमाणु निरोध पर वाशिंगटन घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाने के साथ, राष्ट्रपति यून सुक-योल ने इसे परमाणु निरोध पर आधारित एक नए प्रतिमान के लिए यूएस-कोरिया गणराज्य सुरक्षा गठबंधन के उन्नयन के रूप में घोषित किया।[7] उनकी सक्रिय रणनीतिक आउटरीच और सुरक्षा पहल की गति पर आधारित होते हुए यूं सुक-येओल के अधीन कोरिया गणराज्य सरकार ने अपनी आधिकारिक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (एनएसएस) [8] 7 जून 2023 को[9] जारी की। वैसे तो, यह शोध समझने का प्रयास करेगा कि क्या कोरिया गणराज्य की विदेश नीति में तीव्र नहीं तो कम से कम क्रमिक प्रगति या निरंतरता आई है ताकि भू-राजनीति की बदलती अंतर्धाराओं के बीच एक बड़ी वैश्विक रणनीतिक भूमिका के लिए दावा पेश किया जा सके।

यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि कोरिया गणराज्य को वैश्विक ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए अतीत में काफी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ा जहां वह आज खड़ा है।

---

6 Steve Inskeep and Anthony Kuhn, 2022, "South Korean President Yoon Suk Yeol to hold meetings with President Biden", *NPR*, 26 April 2023, https://www.npr.org/2023/04/26/1172113888/south-korean-president-yoon-suk-yeol-to-hold-meetings-with-president-biden

7 *Korea JoongAng Daily*, 2023, "Yoon Suk Yeol says Washington Declaration upgrades alliance", 2 May 2023, https://koreajoongangdaily.joins.com/2023/05/02/national/diplomacy/KoreaUS-summit-Yoon-Suk-Yeol-Washington-Declaration/20230502183306402.html

8 *Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea*, 2023, "The Yoon Suk Yeol Administration's National Security Strategy: Global Pivotal State for Freedom, Peace, and Prosperity", 8 June 2023, https://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_25772/view.do?seq=16&page=1

9 *Korea JoongAng Daily*, 2023, "Yoon government releases first security strategy paper", 7 June 2023, https://koreajoongangdaily.joins.com/2023/06/07/national/politics/Korea-National-Security-Strategy-Yoon-Suk-Yeol/20230607184116614.html

इसलिए यह अध्ययन मून जे-इन के कार्यकाल से लेकर यूं सुक-योल के राष्ट्रपति पद तक कोरिया गणराज्य के विदेश नीति निर्णयों का विश्लेषण करता है।

शीत युद्ध और उससे उत्पन्न कोरियाई युद्ध के इतिहास के साथ, कोरिया गणराज्य संयुक्त राज्य अमेरिका का गठबंधन भागीदार बन गया। परिणामस्वरूप, सियोल की नीति प्रतिक्रियाओं को अमेरिका के साथ जोड़ना पड़ा। इसके अतिरिक्त, चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति और आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप कोरिया गणराज्य एक बार फिर अमेरिका, चीन और यहां तक कि जापान जैसी प्रमुख शक्तियों के बीच फंस गया है। किसी भी राष्ट्र-राज्य की विदेश नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अपनी भूमिका को बढ़ाने के लिए रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने की क्षमता से होती है, जो अक्सर उन बाधाओं से बाधित होता है जो आंतरिक और सहायक दोनों कारणों का संयोजन होते हैं।[10]

यह शोध कोरिया गणराज्य के वैश्विक संबंधों की खोज पर उपलब्ध स्कॉलरशिप से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। सामान्य परिणाम प्रस्तावों में, विदेश नीति का निर्माण और सुदृढ़ीकरण किसी राष्ट्र-राज्य की घरेलू आवश्यकताओं, क्षेत्रीय शक्तियों और उसकी वैश्विक प्रतिबद्धताओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता को दर्शाता है। इसके बाद प्रगति या निरंतरता के स्पेक्ट्रम के माध्यम से इसकी खोज को प्रमाणित किया जाता है। इसलिए यह अध्ययन मून जे-इन के कार्यकाल से लेकर यूं सुक-योल के राष्ट्रपति पद तक कोरिया गणराज्य के विदेश नीति निर्णयों का विश्लेषण करता है। यह पता लगाता है कि क्या कोरिया गणराज्य की विदेश नीति निर्णय लेने की प्रक्रिया उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा

10 John Bennett Brake, 2022, "Prestige and the Restraint of Power in International Relations", *University of Cambridge*, April 2022, https://doi.org/10.17863/CAM.86969

प्राथमिकताओं, उनकी मध्य शक्ति स्थिति, उनके राष्ट्रीय हितों के विकास और वैश्विक सुरक्षा वातावरण के साथ सामंजस्यपूर्ण रही है। यह शोध पत्र कोरिया गणराज्य के विदेश नीति दृष्टिकोण का इकाई-स्तरीय विश्लेषण पाने के लिए एनएसपी से इंडो-पैसिफ़िक भू-रणनीतिक ढांचे की स्वीकृति तक की अवधि को कवर करता है।

2017 और 2022 के बीच मून जे-इन प्रशासन के अधीन विदेश नीति दृष्टिकोण और यूं सुक-येओल के अधीन वर्तमान प्रशासन को ध्यान में रखते हुए, अध्ययन मुख्य रूप से तीन खंडों की पड़ताल करता है जिन पर इस शोध के लिए कोरिया गणराज्य की विदेश नीति दृष्टिकोण को आधार बनाया जा रहा है। पहला खंड इस बात की जांच करता है कि कोरिया गणराज्य ने हाल के दिनों में अपनी विदेश नीति की सीमाओं के भू-राजनीतिक विस्तार को कैसे देखा। दूसरा खंड कोरिया गणराज्य की विदेश नीति उपायों के संदर्भ में दिखता है, जिसे स्वायत्तता और गठबंधन कूटनीति के क्रॉसरोड्स पर डिज़ाइन किया गया है क्योंकि यह मध्य शक्ति की स्थिति से "वैश्विक निर्णायक राज्य" में विकसित होता है। यह कोरिया गणराज्य की विदेश नीति के दृष्टिकोण में परिवर्तन, प्रगति और निरंतरता पर प्रकाश डालता है। यह कोरिया गणराज्य की विदेश नीति के दृष्टिकोण के संदर्भ में विस्तार से चर्चा करता है, अध्ययन के अनुसार, यह मध्य शक्ति कूटनीति से "वैश्विक निर्णायक राज्य" की आकांक्षा के माध्यम से वैश्विक नेतृत्व के प्रति प्रतिबद्धताओं की राह पर है। तीसरा खंड सुरक्षा, शांति, समृद्धि और विदेशी संबंधों के लिए कोरिया गणराज्य की खोज के साथ जुड़े इंडो-पैसिफ़िक भू-रणनीतिक ढांचे की पड़ताल करता है। चौथा खंड 2017 के बाद से सियोल की विदेश नीति दृष्टिकोण में बदलाव के बीच भारत-कोरिया गणराज्य संबंधों की पड़ताल करता है। अंतिम खंड निष्कर्ष है, जो अध्ययन का अनुमान लगाता है और निष्कर्षों का समग्र विश्लेषण प्रदान करता है। इस प्रकार, अध्ययन बाह्य परिवेश के दृष्टिकोण से कोरिया गणराज्य की विदेश नीति के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करेगा और इस बात पर जोर देगा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली या उस प्रणाली की

21वीं सदी में, अपने लोकतंत्रीकरण और आर्थिक वैश्वीकरण की शुरुआत के परिणामस्वरूप, कोरिया गणराज्य ने अपनी घरेलू नीतियों में गतिशील परिवर्तन किए, जिनके परिणामस्वरूप इसके विदेश नीति दृष्टिकोण को नया आकार देने में मदद मिली।

संरचना ने कोरिया गणराज्य की विदेश नीति को कैसे आकार दिया है।

1. कोरिया गणराज्य की विदेश नीति सीमाओं का भूराजनीतिक विस्तार

1948 में कोरिया गणराज्य सरकार की स्थापना के बाद से पिछले 70 से अधिक वर्षों में, देश ने खुद को सबसे गरीब देशों में से एक से एक आर्थिक महाशक्ति और उदार लोकतंत्र के एक उदाहरण में बदल दिया है।[11] जिसके परिणामस्वरूप, कोरिया गणराज्य राष्ट्रीय शक्ति रूप में काफी बढ़ गया है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में इसे एक मध्य शक्ति माना जाता है।[12] 21वीं सदी में, इसके लोकतंत्रीकरण और आर्थिक वैश्वीकरण की शुरुआत के परिणामस्वरूप, कोरिया गणराज्य ने अपनी घरेलू नीतियों में गतिशील परिवर्तन किए, जिसके परिणामस्वरूप उसकी विदेश नीति के दृष्टिकोण को नया आकार देने में मदद मिली।

2017 से हाल के अतीत पर इस अध्ययन का ध्यान केंद्रित करते हुए, शोध की शुरुआत इस बात से होती है कि कैसे कोरिया गणराज्य ने मून जे-इन प्रशासन के अधीन अमेरिका के साथ अपने गठबंधन पर

11 *Korean Culture and Information Service (KOCIS)*, 2022, "Transition to a Democracy and Transformation into an Economic Powerhouse", https://www.korea.net/AboutKorea/History/Transition-Democracy-Transformation-Economic-Powerhouse

12 YH Kim, 2019, "Diplomatic Achievement of the Republic of Korea and Challenges in the Twenty-First Century", In: *South Korea's 70-Year Endeavor for Foreign Policy, National Defense, and Unification*, Palgrave Macmillan: Singapore, https://doi.org/10.1007/978-981-13-1990-7_3

कम निर्भरता के माध्यम से कुछ हद तक स्वायत्तता का प्रयोग करना शुरू किया। ऐसा प्रतीत होता है कि सियोल बैंडवैगनिंग के पारंपरिक कूटनीतिक तरीकों से हट रहा है। एक मध्य शक्ति के रूप में कोरिया गणराज्य ने वैश्विक और क्षेत्रीय एजेंडों पर विचार किया लेकिन मूर्त रणनीतिक पैंतरेबाज़ी में बाधाओं के साथ। मून जे-इन सरकार ने उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल खतरों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव जुटाने के लिए अपनी पारंपरिक साझेदारी से अलग एक स्वतंत्र मार्ग खोजने का विकल्प चुना। इसने बाहरी प्रभावों के बिना बातचीत पर केंद्रित नीति के माध्यम से प्योंगयांग नेतृत्व को खुश करने की कोशिश की। तब देश ने आसियान और भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के प्रयास में अमेरिका, चीन, रूस और जापान जैसे अपने पारंपरिक व्यापार भागीदारों से परे देखा। एनएसपी को मुख्य रूप से आर्थिक फोकस के साथ एक विविधीकरण पहल के रूप में पेश किया गया था, और इसमें क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीतिक-सुरक्षा मुद्दों को शामिल करने वाली एजेंसियों का अभाव था। इसके बाद, शोध इस बात का पता लगाता है कि मई 2022 में यूं सुक-योल सरकार के सत्ता संभालने के बाद कोरिया गणराज्य की विदेश नीति का दृष्टिकोण एक अधिक इंडो-पैसिफ़िक केंद्रित ढांचे में कैसे विकसित हुआ। राष्ट्रपति यूं सुक-योल ने कोरिया गणराज्य को एक "वैश्विक निर्णायक राज्य" के रूप में विकसित करने की रूपरेखा तय की, जो "सक्रिय रूप से सहयोग के लिए एजेंडे की तलाश करेगा और इंडो-पैसिफ़िक को गले लगाते हुए क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चर्चाओं को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाएगा"।[13] नए दृष्टिकोण को मध्यम शक्ति की अपनी पारंपरिक स्थिति से एक संक्रमण के रूप में देखा जाता है, जो कठोर शक्ति पर प्रक्षेपण पर जोर देता है। विश्व व्यवस्था की बदलती प्रकृति में, राष्ट्रपति यून के नेतृत्व में कोरिया गणराज्य ने अमेरिका, नाटो और यहां तक कि जापान के साथ सहयोग का विस्तार करने और उसे मजबूत करने को प्राथमिकता दी है।

13 *Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea*, 2022, "Strategy for a Free, Peaceful, and Prosperous Indo-Pacific Region", 28 December 2022, https://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5676/view.do?seq=322133&page=1

मून की रणनीतिक अस्पष्टता को त्यागते हुए, राष्ट्रपति यून ने न केवल उत्तर कोरिया बल्कि इंडो-पैसिफ़िक की बढ़ती भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के संबंध में रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर निर्णय लेने के लिए कोरिया गणराज्य के राष्ट्रीय हितों को शामिल किया है।

मून की रणनीतिक अस्पष्टता को त्यागते हुए, राष्ट्रपति यून ने न केवल उत्तर कोरिया बल्कि इंडो-पैसिफ़िक की बढ़ती भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के संबंध में रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर निर्णय लेने के लिए कोरिया गणराज्य के राष्ट्रीय हितों को शामिल किया है।

नई सदर्न पॉलिसी

9 मई 2017 को, डेमोक्रेटिक पार्टी के मून जे-इन ने 41.08 प्रतिशत वोटों के साथ कोरिया गणराज्य के 19वें राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। उन्हें बड़े पैमाने पर राजनीतिक और वित्तीय घोटाले के लिए चुना गया था, जिसके कारण पार्क ग्युन-हे पर महाभियोग चलाया गया था, इस प्रकार कोरिया गणराज्य में एक दशक के रूढ़िवादी शासन का अंत हुआ।[14] भारी जीत के साथ, मून जे-इन ने राजनीतिक-आर्थिक संरचना में सुधार की जनता की मांगों को संबोधित करने की मांग की, उन्होंने पहले इस बात पर जोर दिया था कि उनका लक्ष्य "सुरक्षा, कूटनीति और अर्थव्यवस्था के मौजूदा संकट पर काबू पाना और पुनर्निर्माण" होगा।[15]

राष्ट्रपति मून जे-इन के कार्यकाल की शुरुआत के साथ, कहा गया था कि सियोल उस चीज़ से निपट रहा था जिसे उनका प्रशासन एक स्थिर विदेश और व्यापार

14 Charlie Campbell, 2017, "Moon Jae-in Elected South Korea's New President by Landslide", *Time*, 9 May 2017, https://time.com/4771881/moon-jae-in-president-election-south-korea/

15 *Time*, 2017, "Will South Korean Presidential Hopeful Moon Jae-in Pull the World Back from Nuclear War?", 15 April 2017, https://time.com/4745910/south-korea-elections-moon-jae-in/

नीति मानता था जो केवल कुछ देशों जैसे अमेरिका, चीन, जापान और रूस पर केंद्रित थी। 2015 और 2017 के बीच, यह बताया गया है कि अमेरिका और चीन ने मिलकर कोरिया गणराज्य के कुल निर्यात का 38.1 प्रतिशत हिस्सा लिया, और निर्यात और आयात के कुल मूल्य के संदर्भ में, चीन और अमेरिका ने मिलकर 35 प्रतिशत का योगदान दिया।[16] इसके अलावा, 2016 में THAAD मिसाइल रक्षा प्रणाली की तैनाती के मुद्दे के कारण कोरिया गणराज्य को चीन के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, और ट्रम्प प्रशासन ने अपनी "अमेरिका फर्स्ट" नीति के साथ कोरिया गणराज्य के अमेरिका को निर्यात पर भी रोक लगा दी थी। THAAD की तैनाती उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु परीक्षणों और मिसाइल प्रक्षेपण के बढ़ते खतरों के खिलाफ एक निवारक क्षमता पेश करने के लिए थी। हालाँकि, मून जे-इन प्रशासन के अधीन, THAAD चीन और उत्तर कोरिया के प्रति दृष्टिकोण में बाधा बन गया। THAAD पर राजनयिक विवाद के कारण चीन ने कोरिया गणराज्य पर यात्रा प्रतिबंध भी लगा दिया था। उत्तर कोरिया के संबंध में, राष्ट्रपति मून जे-इन की नीति बातचीत पर केंद्रित थी जो तनाव को कम करने के लिए उत्तर कोरिया के साथ बातचीत में शामिल होने का प्रयास करती थी, जो मून जे-प्रेसीडेंसी के शुरुआती दिनों के दौरान थोड़े समय के लिए THAAD परिनियोजन की परिणामी समीक्षा में आगे जोड़ा गया। ट्रम्प प्रशासन के शामिल होने से व्यापार को प्रभावित करने वाले संरक्षणवादी उपायों की "अमेरिका फर्स्ट" नीति के अलावा, अमेरिका-चीन व्यापार प्रतिद्वंद्विता में भी वृद्धि हुई। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने लंबे समय से चीन पर अनुचित व्यापारिक प्रथाओं और बौद्धिक संपदा की चोरी का आरोप लगाने के साथ, ट्रम्प प्रेसिडेंसी ने बयानबाजी को बढ़ाने और अंततः चीन पर टैरिफ और व्यापार बाधाएं लगाने के लिए दरवाजे खोल दिए।

16 Sungil Kwak, 2018, "Korea's New Southern Policy: Vision and Challenges", *Korea Institute for International Economic Policy*, 12 November 2018, https://think-asia.org/bitstream/handle/11540/9407/KIEPopinions_no146.pdf?sequence=1

इस तरह के परिदृश्य ने कोरिया गणराज्य पर अमेरिका और चीन के बीच कूटनीतिक रूप से संतुलन बनाने का और दबाव बनाया।

चीन के कोरिया गणराज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और अमेरिका उसका संधि गठबंधन भागीदार होने के साथ, कोरिया गणराज्य अमेरिका और चीन के व्यापार युद्ध के बीच संतुलन बनाने में फंस गया था, जिसके लंबा खिंचने की संभावना थी। विशेष रूप से व्यापार के मामले में कुछ देशों पर निर्भरता ने कोरिया गणराज्य को अतिसंवेदनशील बना दिया, जिससे मून जे-इन प्रशासन को अपनी विदेश नीति के लिए एक अलग दृष्टिकोण के साथ आना पड़ा। इसलिए मून जे-इन प्रशासन ने "विश्वास के साथ अपने मुनाफे को अधिकतम करने" के लिए अपनी विदेश नीति में विविधता लाने की मांग की।[17] कोरिया गणराज्य के भू-राजनीतिक विस्तार और विशेष रूप से दक्षिणी क्षेत्रों के साथ इसके सहयोग के दायरे का विस्तार करने के लिए राष्ट्रपति मून जे-इन द्वारा नवंबर 2017 में एनएसपी लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य अमेरिका और चीन के साथ संबंध बनाए रखते हुए भारत और आसियान के साथ दक्षिण कोरिया के संबंधों को मजबूत करना था। एनएसपी का मूल्यांकन कोरिया गणराज्य की विदेश नीति के दृष्टिकोण में एक रणनीतिक बदलाव के रूप में किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर एशिया में अमेरिका, चीन, जापान और रूस के अपने पारंपरिक भागीदारों से परे दक्षिण कोरिया के राजनयिक और आर्थिक संबंधों में विविधता लाना और इसे भारत और आसियान पर ध्यान केंद्रित करने वाले नए दक्षिणी क्षेत्रों के साथ संतुलित करना है।

मून जे-इन प्रशासन की एनएसपी को अपनाने की रणनीति को वैश्विक समाज के अधिक इंडो-पैसिफ़िक भू-रणनीतिक अभिविन्यास की ओर बढ़ने के साथ गलत तरीके से देखा गया।

17 Sungil Kwak, 2018, "Korea's New Southern Policy: Vision and Challenges", *Korea Institute for International Economic Policy*, 12 November 2018, https://think-asia.org/bitstream/handle/11540/9407/KIEPopinions_no146.pdf?sequence=1

हालाँकि, एनएसपी को अपनाने की मून जे-इन प्रशासन की रणनीति को वैश्विक समाज के अधिक इंडो-पैसिफ़िक भू-रणनीतिक अभिविन्यास की ओर बढ़ने के साथ गलत तरीके से देखा गया था। दिवंगत प्रधान मंत्री शिंजो आबे के नेतृत्व में जापान ने अगस्त 2016 में केन्या में "स्वतंत्र और खुली इंडो-पैसिफ़िक रणनीति" को यह कहकर मजबूत किया था कि"जापान प्रशांत और हिंद महासागरों और एशिया और अफ्रीका के संगम को एक ऐसे स्थान में बढ़ावा देने की जिम्मेदारी लेता है जो स्वतंत्रता, कानून के शासन और बाजार अर्थव्यवस्था को महत्व देता है, बल या दबाव से मुक्त है, और इसे समृद्ध बनाता है"।[18] ऑस्ट्रेलिया ने 2017 में इंडो-पैसिफ़िक भू-रणनीतिक अवधारणा को अपनाया था, जैसा कि उनके विदेश नीति श्वेतपत्र,19 में प्रकाशित हुआ था, [19] जिसके बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प के प्रशासन ने नवंबर 2017 में वियतनाम के राजकीय दौरे के दौरान "स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफ़िक" के लिए एक दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार की।[20] बदलाव को जारी रखते हुए, जून 2018 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर में आयोजित शांगरी-ला डायलॉग के दौरान इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया।[21] इसके बाद, आसियान समूह ने जून 2019 में बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित आसियान वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (एसओएम) में "इंडो-पैसिफ़िक पर आसियान आउटलुक" को अपनाया।[22]

---

18 Abe Shinzo, 2016, “Address by Prime Minister Shinzo Abe at the Opening Session of the Sixth Tokyo International Conference on African Development (TICAD VI)”, *Ministry of Foreign Affairs of Japan*, 27 August 2016, https://www.mofa.go.jp/afr/af2/page4e_000496.html

19 *Australian Government*, 2017, “Foreign Policy White Paper”, 23 November 2017, https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/minisite/static/4ca0813c-585e-4fe1-86eb-de665e65001a/fpwhitepaper/foreign-policy-white-paper/prime-ministers-introduction.html

20 *Department of State*, *United States of America*, 2019, “A Free and Open Indo-Pacific”, 4 November 2019, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/11/Free-and-Open-Indo-Pacific-4Nov2019.pdf

21 *Ministry of External Affairs*, *Government of India*, 2020, “Indo-Pacific Division Briefs”, 7 February 2020, https://mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Indo_Feb_07_2020.pdf

22 *ASEAN*, 2019, “ASEAN Outlook on the Indo-Pacific”, 22 June 2019, https://asean.org/asean2020/wp-content/uploads/2021/01/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific_FINAL_22062019.pdf

राष्ट्रपति मून जे-इन के अधीन दक्षिण कोरिया के प्रशासन को नवंबर 2017 में अमेरिका और कोरिया गणराज्य के बीच एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में इंडो-पैसिफ़िक के उल्लेख को स्वीकार करने में बहुत झिझक और अनिच्छा थी।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति मून जे-इन के अधीन दक्षिण कोरिया के प्रशासन को नवंबर 2017 में अमेरिका और कोरिया गणराज्य के बीच एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में इंडो-पैसिफ़िक के उल्लेख को स्वीकार करने में बहुत झिझक और अनिच्छा थी।[23] प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया था कि इसमें एक खंड है जो कहता है: *"राष्ट्रपति ट्रम्प ने संयुक्त राष्ट्र-कोरिया गणराज्य के गठबंधन पर प्रकाश डाला, जो स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मानवीय अधिकारों और स्वतंत्रता-प्रेम के आपसी विश्वास और साझा मूल्यों पर आधारित है, जो इंडो-पेसिफ़िककी सुरक्षा, सुरक्षा और समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी बनी हुई है।"*[24] हालाँकि, चेओंग वा डे या ब्लू हाउस के एक अधिकारी ने आश्चर्यजनक रूप से टिप्पणी की थी कि बयान में भाग का संयुक्त रूप से उल्लेख नहीं किया गया था, और यहां तक कि सुझाव दिया था कि राष्ट्रपति मून ने "इंडो-पैसिफ़िक" के उल्लेख के लिए अपने नाम पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।[25] नतीजतन, उनकी स्थिति में गिरावट आई और यह स्पष्ट किया गया कि सियोल और वाशिंगटन "इंडो-पेसिफ़िकसंदर्भ में संभावित सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाएंगे"।[26] इस घटना ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया था कि मून जे-इन के अधीन कोरिया गणराज्य की सरकार जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे उत्साही लोगों

23 *Trump White House Archives*, 2017, "Joint Press Release by the United States of America and the Republic of Korea", 8 November 2017, https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/joint-press-release-united-states-america-republic-korea/

24 Koh Byung-joon, 2017, "Trump's 'Indo-Pacific' vision poses dilemma for S. Korea", *Yonhap News Agency*, 10 November 2017, https://en.yna.co.kr/view/AEN20171110004000315

25 Koh Byung-joon, 2017, "Trump's 'Indo-Pacific' vision poses dilemma for S. Korea", *Yonhap News Agency*, 10 November 2017, https://en.yna.co.kr/view/AEN20171110004000315

26 Koh Byung-joon, 2017, "Trump's 'Indo-Pacific' vision poses dilemma for S. Korea", *Yonhap News Agency*, 10 November 2017, https://en.yna.co.kr/view/AEN20171110004000315

के विपरीत इंडो-पैसिफ़िक अवधारणा के प्रति उदासीन थी। मून जे-इन के अधीन सियोल ने गलती से यह समझ लिया था कि "इंडो-पैसिफ़िक" अवधारणा को स्वीकार करने से कोरिया गणराज्य बड़े भू-राजनीतिक मुकाबले में पक्ष चुन लेगा। हालाँकि, 2019 में, मून जे-इन के अधीन कोरिया गणराज्य सरकार ने बहुत कूटनीतिक चालाकी के बाद आखिरकार यह पता लगा लिया कि "इंडो-पैसिफ़िक" अवधारणा को तटस्थ तरीके से कैसे देखा जाए।

30 जून 2019 को, उत्तर कोरिया और अमेरिका को पनमुनजोम में पहली बार एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में आमने-सामने आना पड़ा, कोरिया गणराज्य-अमेरिका शिखर सम्मेलन के बाद, कोरिया गणराज्य और अमेरिका के बीच संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का विशेष उल्लेख किया गया था कि कैसे कोरिया गणराज्य और अमेरिका *"कोरिया की नई साउथ पॉलिसी और यूनीएड सियास के इंडो-पैसिफ़िक सीरियाई के बीच सामंजस्यपूर्ण सहयोग पर सहमत हुए हैं।*[27] गहन आत्मनिरीक्षण करने पर, यह शायद राष्ट्रपति मून जे-इन द्वारा यह संकेत देने के लिए एक छोटी सी पेशकश थी कि कोरिया गणराज्य एक राजनीतिक विरासत छोड़ने की बड़ी योजना में अमेरिका की इंडो-पैसिफ़िक रणनीति को स्वीकार कर सकता है जिसने सियोल और प्योंगयांग के साथ-साथ अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया। हालाँकि, एनएसपी और अमेरिका की इंडो-पैसिफ़िक रणनीति के बीच संरेखण का यह सरल उल्लेख उस देश की अपेक्षा से कम था जो इंडो-पैसिफ़िक भू-रणनीतिक ढांचे के केंद्र में है। राष्ट्रपति मून के अधीन सियोल, यूएस-चाइना नाज़ुक हालात से समान दूरी पर अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए, इंडो-पैसिफ़िक अवधारणा के अपने आधिकारिक संस्करण को प्रख्यापित कर सकता था।

कुल मिलाकर, एनएसपी ने भारत और आसियान के साथ दक्षिण कोरिया के आर्थिक और राजनयिक संबंधों को बढ़ाने के संदर्भ में सकारात्मक परिणाम दिए।

---

27 *Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea*, 2019, "Opening Remarks by President Moon Jae-in at Joint Press Conference Following Korea-U.S. Summit", 30 June 2019, https://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5674/view.do?seq=319902

एनएसपी के तीन पी (लोग, समृद्धि और शांति) के माध्यम से, कोरिया गणराज्य ने अपनी विदेश नीति के दृष्टिकोण को आसियान चार्टर में स्थापित आसियान के जन-केंद्रित मूल्यों के साथ जोड़ा। एनएसपी ने कोरिया गणराज्य को व्यापक क्षेत्रीय व्यापार कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए एक मार्ग प्रदान किया जिसका उद्देश्य पारस्परिक समृद्धि है। एनएसपी का उद्देश्य उच्च तकनीक विनिर्माण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोरिया की व्यावसायीकरण प्रौद्योगिकी और अनुभव के साथ भारत के बुनियादी विज्ञान के उच्च स्तर का लाभ उठाना भी है। इसका उद्देश्य भारत को अपने स्वयं के उच्च-तकनीकी उद्योगों को विकसित करने और इस क्षेत्र में अग्रणी बनने में मदद करना था। हालाँकि, ऐसी चिंताएँ थीं कि एनएसपी पर अन्य क्षेत्रीय पहलों, जैसे कि क्वाड और फ्रीएंडओपन इंडो-पैसिफ़िक (एफओआईपी) का प्रभाव पड़ सकता है। मून जैन प्रशासन के दौरान क्वाड या एफओआईपी के प्रति अपने नेविगेशन में सियोल का दृष्टिकोण उत्साह से कम होने के कारण यह दुविधा और भी बढ़ गई थी।[28]

नई सादर्न पॉलिसी प्लस

2020 तक, इस क्षेत्र के और बाहर के कई देशों द्वारा इंडो-पैसिफ़िक के बारे में अपनी अवधारणाओं और दृष्टिकोण को रेखांकित करने के बाद भी, मून जे-इन के अधीन कोरिया गणराज्य ने नवंबर 2020 में 21वें आसियान-कोरिया गणराज्य वर्चुअल शिखर सम्मेलन में एक उन्नत एनएसपी को नई सदर्न पॉलिसी प्लस (एनएसपी प्लस) के रूप में पेश करने का निर्णय लिया।[29] यह प्रगति तब भी हुई जब एनएसपी के केंद्र आसियान और भारत ने इंडो-पैसिफ़िक के प्रति अपने दृष्टिकोण/दृष्टिकोण और दृष्टिकोण की घोषणा की थी।

28 Jiye Kim and Thomas Wilkins, 2020, "South Korea and America's Indo-Pacific Strategy: Yes, But Not Quite", *Fulcrum*, 26 November 2020, https://fulcrum.sg/south-korea-and-americas-indo-pacific-strategy-yes-but-not-quite/

29 *ASEAN*, 2020, "Chairman's statement of the 21st ASEAN-Republic of Korea Summit", 12 November 2020, https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/52-Final-Chairmans-Statement-of-the-21st-ASEAN-ROK-Summit.pdf

स्वाभाविक रूप से, लगातार सवाल उठते रहे कि एक केंद्रीय इंडो-पैसिफ़िक राष्ट्र होने के नाते कोरिया गणराज्य एक सौहार्दपूर्ण एनएसपी प्लस के साथ क्यों जारी रहा और इंडोपैसिफ़िक अवधारणा के अपने दृष्टिकोण की वकालत करने में देरी क्यों की। इसके अलावा, संदेह पैदा हुआ कि क्या एनएसपी प्लस में कोई मूल्यवर्धन था या यह पिछले एनएसपी की पुनरावृत्ति मात्र थी, जिसमें केवल एक "प्लस" था जो कि कोविड19 महामारी के कारण स्वास्थ्य देखभाल सहयोग को पूरा करता था।

कोविड-19 महामारी की शुरुआत ने वैश्विक समुदाय के लिए अभूतपूर्व परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दीं। 21वीं सदी की विदेश नीतियों में आम पारंपरिक ज्ञान और तर्क पर फिर से विचार करना होगा और उसका पुनर्मूल्यांकन करना होगा। महामारी के ऊपर, अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता में कोई राहत नहीं दिख रही थी। पूर्व और दक्षिण चीन सागर में यथास्थिति को बलपूर्वक बदलने के प्रयासों के माध्यम से, इंडो-पेसिफ़िकक्षेत्र में क्षेत्रीय संप्रभुता और अखंडता के संदर्भ में तनाव बढ़ रहा था। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण मानव संसाधनों और वस्तुओं के मुक्त प्रवाह पर प्रतिबंध ने डिजिटल अर्थव्यवस्था के माध्यम से व्यावसायिक लेनदेन के लिए नए तरीकों के महत्व पर प्रकाश डाला और प्रोत्साहित किया। आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के कारण यह एहसास हुआ कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को विविधीकृत, पुनर्गठित और लचीला बनाने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोविड-19 महामारी ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से एक बेहतर और मजबूत स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

जैसे, जब मून जे-इन के अधीन कोरिया गणराज्य ने एनएसपी का उन्नत संस्करण एनएसपी प्लसइननवंबर2020 के रूप में पेश किया, उन्होंने ऐसा कोविड-19 महामारी के कारण भूराजनीति में बदलाव के बाद उभरी विभिन्न कमियों की भरपाई के लिए कुछ रणनीतिक पहलों की घोषणा करने के लिए किया।

इंडो-पैसिफ़िक अवधारणा के सियोल संस्करण को जारी किए बिना, लेकिन यूएस इंडोपैसिफ़िक रणनीति के साथ उन्नत एनएसपी प्लस के अधीन सहयोग के संभावित क्षेत्रों को संरेखित करते हुए, मून जे-इन के अधीन कोरिया गणराज्य प्रशासन ने अमेरिका या चीन का पक्ष लिए बिना, विशेष रूप से बढ़ते आर्थिक और भू-राजनीतिक तनाव के बीच, हेजिंग प्लेटफॉर्म को अपनाया।

बड़े पैमाने पर सार्वजनिक स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, व्यापार और निवेश, ग्रामीण और शहरी बुनियादी ढांचे के विकास, भविष्य के उद्योगों के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर सहयोग शामिल है। हालाँकि ये पहल कई अन्य इंडो-पैसिफ़िक देशों के दृष्टिकोण के समान लग रही थी, मून जे-इन के अधीन कोरिया गणराज्य ने एनएसपी प्लस में सहयोग के क्षेत्रों को बड़े करीने से पैक किया और इसे अमेरिका जैसे देशों की विभिन्न इंडो-पैसिफ़िक रणनीति पहलों के अनुरूप प्रदर्शित किया। इस तरह, राष्ट्रपति मून के अधीन कोरिया गणराज्य अमेरिका के ताबेदार के रूप में पहचाने जाने से बच गया। इस बीच, एनएसपी प्लस सियोल को आसियान और भारत के साथ गहराई से जोड़ने की वकालत करने का एक माध्यम बन गया, जिन्हें इसके पारंपरिक भागीदारों के लिए महत्वपूर्ण विकल्प माना जाता था। इसका मतलब है कि कोरिया गणराज्य ने हेजिंग प्लेटफॉर्म पर प्राथमिकता दी, अपनी नीति के अनुसार दक्षिणी देशों के साथ अपने सहयोग का विस्तार किया।

2020 में एनएसपी प्लस में अपग्रेड करने का निर्णय यह संकेत देने की योजना थी कि राष्ट्रपति मून जे-इन के कार्यकाल के दौरान 2019 में ऐतिहासिक यूएस-उत्तर कोरिया शिखर सम्मेलन के साथ-साथ अंतर-कोरियाई शिखर सम्मेलन के बाद, सियोल यह स्वीकार कर रहा था कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को कायम रखते हुए अपनी संप्रभु विदेश नीति के सहयोग के क्षेत्रों को यूएस-इंडो-पैसिफ़िक रणनीति के साथ जोड़ सकता है।

इस तरह, इंडो-पैसिफ़िक अवधारणा के सियोल संस्करण को जारी किए बिना, लेकिन उन्नत एनएसपी प्लस के अधीन यूएसइंडोपैसिफ़िक रणनीति के अधीन सहयोग के संभावित क्षेत्रों को संरेखित किया गया, मून जे-इन के अधीन कोरिया गणराज्य प्रशासन ने अमेरिका या चीन का पक्ष लिए बिना, विशेष रूप से बढ़ते आर्थिक और भू-राजनीतिक तनाव के बीच, हेजिंग प्लेटफॉर्म को अपनाया।2017 में एनएसपी को अपनाने के निर्णय को "एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया गया, जिसने सियोल की पारंपरिक विदेश नीतियों से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान को चिह्नित किया, और मौजूदा नीतियों के सहयोग के दायरे का विस्तार किया।"[30] 2020 में एनएसपी प्लस में अपग्रेड को स्वायत्तता की डिग्री की दिशा में बदलाव की निरंतरता के रूप में कहा जा सकता है क्योंकि नीति अमेरिका, रूस, चीन और जापान की पारंपरिक प्रमुख शक्तियों के बाहर वैकल्पिक साझेदारी खोजने पर ध्यान केंद्रित करती रही, जो कि कोरिया गणराज्य के संबंधों का मुख्य आधार रही है। हालाँकि, सियोल, उन्नत एनएसपी प्लस को अपनाते समय, एक बार फिर क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों को प्रभावित करने वाले विभिन्न अंतर्निहित सुरक्षा विचारों को याद कर रहा था।

एनएसपी और एनएसपी प्लस रणनीतियाँ जो सियोल की साझेदारियों को उसके पारंपरिक सहयोगों से अलग करने के लक्ष्य के साथ आर्थिक पहलुओं पर आधारित थीं, यूके हीओ और टेरेंस रोह्रिग (2014) के विश्लेषण की याद दिलाते हैं कि आर्थिक विकास विदेशी संबंधों को कैसे प्रभावित करता है।[31] विस्तार से कहें तो, सियोल आर्थिक समृद्धि का गवाह बन रहा था लेकिन अमेरिका, चीन, जापान और रूस पर अत्यधिक निर्भरता, विशेष रूप से वैश्विक उतार-चढ़ाव के बीच, कोरिया गणराज्य को अपने आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए अपनी विदेश नीति पर फिर से विचार करने की आवश्यकता पड़ी।

---

30 Choe Wongi, 2023, "South Korea's New Southern Policy: The Limits of Indo-Pacific Geopolitics", in Lam Peng Er. (ed.) *South Korea's New Southern Policy: A Middle Power's International Relations with Southeast Asia and India*, pp. 19-41, New York: Routledge

31 U Heo and T Roehrig, 2014, *South Korea's Rise: Economic Development, Power, and Foreign Relations*, Cambridge: Cambridge University Press, doi:10.1017/CBO9780511998355

इसलिए, एक बदलाव को बढ़ावा देने के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अधिक भागीदारी हुई, इसके हितों का विस्तार हुआ और एनएसपी और बाद में एनएसपी प्लस के माध्यम से अपने विदेश नीति लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए उपकरणों में वृद्धि हुई।

मून जे-इन के अधीन कोरिया गणराज्य विदेश नीति में बदलावों का समर्थन करने वाला एक और दृष्टिकोण वोनजेह्वांग (2017) से आता है। वह बताते हैं कि लोकतंत्रीकरण और आर्थिक वैश्वीकरण ने कोरिया गणराज्य में घरेलू राजनीति को बदल दिया और इसकी विदेशी नीतियों को नया आकार दिया। लेखक का तर्क है कि कोरिया गणराज्य द्वारा अपनाई गई स्वतंत्र और सक्रिय विदेश नीति लोकतंत्र और आर्थिक वैश्वीकरण के प्रभाव की स्वीकृति थी। इसका परिणाम रणनीतिक निर्णय लेने में स्वायत्तता का आधार है, जो चीन और अमेरिका के साथ संबंधों को आगे बढ़ाते हुए उदारवादी पार्टियों की विदेश नीति के दृष्टिकोण का मुख्य आधार था। आसियान और भारत के माध्यम से घनिष्ठ संबंध को बढ़ावा देने की रूपरेखा पर आधारित, मून जे-इन प्रशासन ने अमेरिका, चीन, रूस और जापान को संतुलित करने के लिए एनएसपी और एनएसपी प्लस की नीतियों को अपनाया, जिन्होंने परंपरागत रूप से कोरिया गणराज्य के विदेशी मामलों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। हालाँकि, इसका मतलब यह भी था कि कोरिया गणराज्य अमेरिका के साथ अपनी पारंपरिक गठबंधन साझेदारी से दूर जाने को तैयार था, जिसके विस्तारित प्रतिरोध के अधीन सियोल 1953 में कोरियाई युद्ध की समाप्ति के बाद से पारंपरिक रूप से बाहरी आक्रमणों से खुद को बचाने के लिए भरोसा कर रहा था।

वैश्विक निर्णायक राज्य: स्वतंत्र,
शांतिपूर्ण, और समृद्ध इंडो-पैसिफ़िक

मार्च 2022 में हुए 20वें राष्ट्रपति चुनावों के लिए राष्ट्रपति यूं सुक-योल का अभियान कोरिया गणराज्य के कद को "वैश्विक निर्णायक राज्य" के रूप में ऊंचा करने

SMई 2022 में कोरिया गणराज्य के 20वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने और कार्यभार संभालने के तुरंत बाद, राष्ट्रपति यून सुक- येओल ने "वैश्विक निर्णायक राज्य" बनने को कोरिया गणराज्य के अपने एजेंडे को और आगे बढ़ाया

के एजेंडे पर आधारित था।[32] "वैश्विक निर्णायक राज्य" के रूप में विकसित होने का लक्ष्य था कि कोरिया गणराज्य "उदार लोकतांत्रिक मूल्यों और पर्याप्त सहयोग" के आधार पर "स्वतंत्रता, शांति और समृद्धि" को आगे बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित करेगा"।[33] "वैश्विक निर्णायक राज्य" बनने की आकांक्षा का अर्थ यह भी है कि कोरिया गणराज्य सक्रिय रूप से सहयोग के लिए एजेंडा की तलाश करेगा और क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चर्चाओं को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाएगा"।[34] मई 2022 में कोरिया गणराज्य के 20वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने और कार्यभार संभालने के तुरंत बाद, राष्ट्रपति यूं सुक-योल ने 28 दिसंबर 2022 को अपनी आधिकारिक इंडो-पैसिफ़िक रणनीति पेश करके कोरिया गणराज्य को "वैश्विक निर्णायक राज्य" बनने के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाया। दस्तावेज़, "स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और समृद्ध इंडो-पैसिफ़िक के लिए रणनीति", "वैश्विक निर्णायक राज्य" के उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है।[35] इस रणनीति का उद्देश्य इंडो-पैसिफ़िक में दक्षिण कोरिया की भागीदारी को बढ़ाना है,

32 Yoon Suk-yeol, 2022, "South Korea Needs to Step Up", *Foreign Affairs*, 8 February 2022, https://www.foreignaffairs.com/articles/south-korea/2022-02-08/south-korea-needs-step

33 Yoon Suk-yeol, 2022, "South Korea Needs to Step Up", *Foreign Affairs*, 8 February 2022, https://www.foreignaffairs.com/articles/south-korea/2022-02-08/south-korea-needs-step

34 Tunchinmang Langel, 2023, "Deconstructing Republic of Korea's (ROK) 'Strategy for a Free, Peaceful and Prosperous Indo-Pacific' ", *ICWA*, 31 January 2023, https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=8975&lid=5849

35 *Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea*, 2022, "Strategy for a Free, Peaceful, and Prosperous Indo-Pacific Region", 28 December 2022, https://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5676/view.do?seq=322133&page=1

जब राष्ट्रपति यूं सुक-योल की बात आती है, तो उन्होंने गठबंधन के
महत्व को रेखांकित किया है
न केवल अपने पारंपरिक साझेदार अमेरिका, बल्कि लैटिन अमेरिकी देशों,
अफ्रीकी देशों, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, प्रशांत द्वीप देशों आदि
से लेकर लगभग सभी हितधारकों के साथ।

जो "अपने आर्थिक और सुरक्षा महत्व के कारण देश के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।"**36**

कुछ विशेषज्ञ विश्लेषण हैं, जिन्होंने कहा है कि क्या कोरिया गणराज्य को "वैश्विक निर्णायक राज्य" बनने की ज़रूरत है। उनके परिप्रेक्ष्य में वैश्विक निर्णायक राज्य बनने की आवश्यकताओं का अर्थ है विदेश नीति संबंधी निर्णय लेने में क्षमता और स्वायत्तता होना। इस अध्ययन में यह महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति मून जे-इन के कार्यकाल और राष्ट्रपति यूं सुक-योल के राष्ट्रपति पद के बीच की अवधि के इस बात पर प्रकाश डाला जाए कि सभी विदेश नीति निर्णय लेने को उनके संबंधित मामलों में स्वायत्त माना जाता है। मामले में, राष्ट्रपति मून ने कोरिया गणराज्य की पारंपरिक साझेदारी और गठबंधन के विकल्प खोजने का फैसला किया, और उत्तर कोरिया के साथ "पीस फ़र्स्ट" नीति अपनाने का निर्णय लिया। राष्ट्रपति मून ने अमेरिका-चीन द्वंद्व के संबंध में अधिक बचाव मंच की भी वकालत की। राष्ट्रपति मून के अधीन कोरिया गणराज्य की विदेश नीति के दृष्टिकोण में ये सभी स्वायत्त प्रयास थे। इसी तरह, जब राष्ट्रपति यूं सुक-योल की बात आती है, उन्होंने न केवल अपने पारंपरिक साझेदार अमेरिका बल्कि लैटिन अमेरिकी देशों, अफ्रीकी

36 Tunchinmang Langel, 2023, "Deconstructing Republic of Korea's (ROK) 'Strategy for a Free, Peaceful and Prosperous Indo-Pacific' ", *ICWA*, 31 January 2023, https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=8975&lid=5849

यहां तक कि एक आधिकारिक कोरियाई इंडो-पैसिफ़िक रणनीति की वकालत करने में सक्षम होना विदेश नीति दृष्टिकोण में स्वायत्त सोच का एक उदाहरण है। यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि सिर्फ इसलिए कि एक भू-रणनीतिक अवधारणा को इंडो-पैसिफ़िक के एक स्थापित शब्दकोष द्वारा जाना जाता है, यह किसी भी संदर्भ में यह निर्धारित नहीं करता है कि राष्ट्र-राज्य अपने विश्वदृष्टिकोण से नीति के अपने संस्करण को प्रख्यापित कर रहे हैं, वे उसी अमेरिकी अम्ब्रेला के अंतर्गत आएंगे।

देशों, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, प्रशांत द्वीप देशों आदि से लेकर लगभग सभी हितधारकों के साथ गठबंधन और साझेदारी के महत्व को रेखांकित किया है। यह इस बात पर विचार करते हुए महत्वपूर्ण है कि कोरिया गणराज्य का दृष्टिकोण आम तौर पर और पारंपरिक रूप से पूर्वोत्तर एशिया पर केंद्रित था। हालाँकि, राष्ट्रपति यून ने उन सभी लोगों को आमंत्रित करने के लिए देश की स्वायत्तता का उपयोग करने का निर्णय लिया, जो कोरिया गणराज्य की बढ़ती आयु को पहचानने के लिए मूल्यों और हितों को साझा करते हैं। यहां तक कि एक आधिकारिक कोरियाई इंडो-पैसिफ़िक रणनीति की वकालत करने में सक्षम होना विदेश नीति दृष्टिकोण में स्वायत्त सोच का एक उदाहरण है। यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि सिर्फ इसलिए कि एक भू-रणनीतिक अवधारणा को इंडो-पैसिफ़िक के एक स्थापित शब्दकोष द्वारा जाना जाता है, यह किसी भी संदर्भ में यह निर्धारित नहीं करता है कि अपने विश्वदृष्टिकोण से नीति के अपने संस्करण को प्रख्यापित करने वाले राष्ट्र-राज्य उसी अमेरिकी छत्र के अंतर्गत आएंगे। वर्षों के बाद कोरिया गणराज्य के पास अंततः इंडो-पैसिफ़िक निर्माण का अपना आधिकारिक संस्करण है, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, आसियान, यूरोपीय संघ और अन्य के पास भी है।

क्षमता के संदर्भ में भी, अनुसंधान ने विश्लेषण किया कि कैसे कोरिया गणराज्य मून जे-इन और यूं सुक-योल दोनों के अनुसार, क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम है। फर्क सिर्फ इतना रहा है कि क्या नेतृत्व खुले तौर पर अपनी क्षमता की

वकालत करना चाहता था। यह हमें एक अन्य पहलू या आवश्यकता पर भी लाता है, जो क्षमता है। दोनों शब्दावलियों का अक्सर एक ही रूप में दुरुपयोग किया जाता है, लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि क्षमता का तात्पर्य भौतिक संसाधनों से है, जबकि क्षमता का तात्पर्य देश की अपने भौतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता से है। युद्ध के संदर्भ में, क्षमता हथियार और गोला-बारूद होगी, और क्षमता को इस रूप में परिभाषित किया जाता है कि सशस्त्र बल के जवान इन उपकरणों को प्रभावी ढंग से और सक्षम रूप से संचालित करने में सक्षम हैं या नहीं।

क्षमता और स्वायत्तता के तर्क को आगे के संदर्भ में रखने के लिए कि क्या कोरिया गणराज्य खुद को "वैश्विक निर्णायक राज्य" के रूप में प्रोजेक्ट करने के लिए इन मानदंडों को पूरा करता है आइए हम उन संयुक्त सैन्य अभ्यासों के बारे में जानें जो अमेरिका और कोरिया गणराज्य के बीच एक नियमित विशेषता थी। राष्ट्रपति मून जे-इन के अधीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और कोरिया गणराज्य ने 2018 से यूएस-कोरिया गणराज्य संयुक्त सैन्य अभ्यास को रद्द कर दिया था या उसके पैमाने को कम कर दिया था, ताकि उत्तर कोरिया के साथ बातचीत की प्रगति का जायजा लिया जा सके। हालाँकि, यह जल्द ही स्पष्ट हो गया कि कूटनीति केवल यहीं तक आगे बढ़ी है। 2019 में, उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं का परीक्षण पूरी तरह से फिर से शुरू कर दिया था। किम और ट्रम्प के बीच परमाणु निरस्त्रीकरण पर आयोजित अनुवर्ती शिखर सम्मेलन के बीच भी, 2019[37] में कुल 26 परीक्षण लॉन्च हुए।

राष्ट्रपति मून के अधीन कोरिया गणराज्य अपने प्रभावी और नियमित संयुक्त सैन्य अभ्यास को रद्द करके या कम करके अमेरिका से अलगाव को समायोजित कर रहा था, जो उनके सशस्त्र बलों की क्षमता निर्माण और क्षमता वृद्धि के लिए पवित्र थे।

37 *Nuclear Threat Initiative*, 2023, "The CNS North Korea Missile Test Database", 28 April 2023, https://www.nti.org/analysis/articles/cns-north-korea-missile-test-database/

मून जे-इन की पीस फ़र्स्ट पॉलिसी वास्तव में एक उल्लेखनीय दृष्टिकोण थी, लेकिन इससे यह भी पता चल रहा था कि उत्तर में एक अप्रत्याशित सत्तावादी नेता के कारण कोरिया गणराज्य कितना असुरक्षित है। राष्ट्रपति मून के अधीन कोरिया गणराज्य अपने प्रभावी और नियमित संयुक्त सैन्य अभ्यास को रद्द करके या कम करके अमेरिका से सैनिकों की वापसी को समायोजित कर रहा था, जो उनके सशस्त्र बलों की क्षमता निर्माण और क्षमता वृद्धि के लिए पवित्र थे। यह कहा जा सकता है कि यह दृष्टिकोण स्वायत्तता पर गलत प्राथमिकता से आया है, जबकि इसके पास कोई अन्य विश्वसनीय विकल्प भी नहीं था।

2022 से, यून प्रशासन की स्थापना के बाद से दोनों देश अभ्यास के दायरे और पैमाने का विस्तार कर रहे हैं। नियमित संयुक्त सैन्य अभ्यासों को इस प्रकार विभाजित किया गया है कि फ्रीडम शील्ड (एफएस) अभ्यास वर्ष की पहली छमाही में आयोजित किया जाता है और उल्ची फ्रीडम शील्ड (यूएफएस) अभ्यास उत्तरार्ध में आयोजित किया जाता है। इस विशेष रि-एंगेजमेंट ने इस बात पर जोर दिया है कि कैसे कोरिया गणराज्य को अपनी क्षमता और सामर्थ्य बढ़ाने की जरूरत है, खासकर तब जब उसका उत्तरी पड़ोसी अपनी परमाणु प्रौद्योगिकी और बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता और क्षमताओं में लगातार सुधार और उन्नयन कर रहा है। इसके अलावा, अपनी स्वायत्तता प्रदर्शित करने के लिए, राष्ट्रपति यून के अधीन कोरिया गणराज्य 2023 में व्यक्तिगत रूप से तैयार साझेदारी कार्यक्रम (आईटीपीपी) के माध्यम से जापान के साथ संबंधों को पुनः व्यवस्थित करने, कोरिया गणराज्य-अमेरिका गठबंधन को बढ़ाने, कोरिया गणराज्य-अमेरिका-जापान त्रिपक्षीय सुरक्षा सहयोग को संस्थागत बनाने और नाटो के साथ गहरी साझेदारी विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ा है।

इंडो-पैसिफ़िक के लिए अपनी नई रणनीति जारी करने के बाद कोरिया गणराज्य ने खुद को इंडो-पैसिफ़िक राष्ट्र घोषित कर दिया। इंडो-पैसिफ़िक के लिए अपने रणनीति दस्तावेज़ के माध्यम से, सियोल

कोरिया गणराज्य द्वारा इंडो-पैसिफ़िक रणनीति की घोषणा के परिणामस्वरूप "अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक व्यापक क्षेत्रीय रणनीति" का अनावरण किया गया है।

ने विशेष रूप से इंडो-पैसिफ़िक के महत्व की वकालत की है क्योंकि यह "कई प्रमुख रणनीतिक शिपिंग मार्गों का घर है, जिस पर कोरिया गणराज्य के व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निर्भर है"।[38] दक्षिण चीन सागर को स्पष्ट रूप से "प्रमुख समुद्री मार्ग" के रूप में वर्णित किया गया है, जो कोरिया गणराज्य के कच्चे तेल परिवहन और प्राकृतिक गैस परिवहन का क्रमशः लगभग 64 प्रतिशत और 46 प्रतिशत हिस्सा है।[39] उत्तर कोरिया के परमाणु प्रसार और मिसाइल क्षमताओं की प्रगति को अब न केवल कोरियाई प्रायद्वीप के लिए बल्कि इंडो-पेसिफ़िकसहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी ख़तरे के रूप में देखा जा रहा है।[40] इंडो-पैसिफ़िक रणनीति दस्तावेज़ इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र पर वैश्विक समुदाय की तकनीकी निर्भरता पर भी जोर देता है, जो सेमीकंडक्टर्स के निर्माण में शामिल रणनीतिक उद्योगों के लिए प्रमुख भागीदारों की मेजबानी करता है। कोरिया गणराज्य द्वारा इंडो-पैसिफ़िक रणनीति की घोषणा के परिणामस्वरूप "अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक व्यापक क्षेत्रीय रणनीति" का अनावरण किया गया है"।[41]

इंडो-पैसिफ़िक रणनीति दस्तावेज़ का दूसरा भाग यह भी इंगित करता है कि कोरिया गणराज्य की विदेश नीति क्षेत्रीय सीमा

38 *Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea*, 2022, "Strategy for a Free, Peaceful, and Prosperous Indo-Pacific Region", 28 December 2022, https://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5676/view.do?seq=322133&page=1

39 *Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea*, 2022, "Strategy for a Free, Peaceful, and Prosperous Indo-Pacific Region", 28 December 2022, https://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5676/view.do?seq=322133&page=1

40 *Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea*, 2022, "Strategy for a Free, Peaceful, and Prosperous Indo-Pacific Region", 28 December 2022, https://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5676/view.do?seq=322133&page=1

41 Tunchinmang Langel, 2023, "Deconstructing Republic of Korea's (ROK) 'Strategy for a Free, Peaceful and Prosperous Indo-Pacific' ", *ICWA*, 31 January 2023, https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=8975&lid=5849

मून जे-इन के एनएसपी दृष्टिकोण के बाद से विकसित हुई है। रणनीति दस्तावेज़ ने स्पष्ट रूप से कोरियाई प्रायद्वीप और पूर्वोत्तर एशिया के दायरे से परे अपने राजनयिक क्षितिज के विस्तार की वकालत की है। उम्मीद है कि कोरिया गणराज्य दक्षिण-पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, हिंद महासागर के अफ्रीकी तट को शामिल करते हुए हिंद-प्रशांत में महत्वपूर्ण देशों के साथ रणनीतिक सहयोग तेज करेगा। साझेदारी की इस गहनता को "अंततः इंडो-पेसिफ़िकके लिए सहयोग की रूपरेखा बनाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र के लिए तैयार रणनीतिक साझेदारी के नेटवर्क" के माध्यम से लक्षित किया जाएगा।[42] कोरिया गणराज्य "शांतिपूर्ण और समृद्ध इंडो-पैसिफ़िक" को बढ़ावा देने के लिए यूरोप और लैटिन अमेरिका के साथ मिलकर काम करने पर भी उत्सुक है"।[43] कोरिया गणराज्य-अमेरिका गठबंधन की पारंपरिक मजबूती के अलावा, यह जापान, कनाडा और मंगोलिया के संबंध में घोषणा है जिसने कोरिया गणराज्य के दृष्टिकोण में आगे बढ़ने का एक नया तरीका जोड़ा है। जापान के साथ समान हितों और मूल्यों पर आधारित भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण अपनाने का महत्व, उत्तर कोरियाई परमाणु ख़तरे के सामने कोरियाई प्रायद्वीप में द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को संभावित रूप से आकार देगा। इसके अतिरिक्त, कनाडा के साथ "व्यापक रणनीतिक साझेदारी" के माध्यम से, कोरिया गणराज्य "स्थिर आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया, आर्थिक सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने की ओर देख रहा है"।[44] इसके अलावा, मंगोलिया के साथ रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने में, कोरिया गणराज्य आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों पर

---

42 *Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea*, 2022, "Strategy for a Free, Peaceful, and Prosperous Indo-Pacific Region", 28 December 2022, https://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5676/view.do?seq=322133&page=1

43 Tunchinmang Langel, 2023, "Deconstructing Republic of Korea's (ROK) 'Strategy for a Free, Peaceful and Prosperous Indo-Pacific' ", *ICWA*, 31 January 2023, https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=8975&lid=5849

44 *Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea*, 2022, "Strategy for a Free, Peaceful, and Prosperous Indo-Pacific Region", 28 December 2022, https://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5676/view.do?seq=322133&page=1

सहयोग को गतिशील रूप से बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है, विशेष रूप से 'दुर्लभ पृथ्वी तत्वों' के संबंध में।[45] चूंकि मंगोलिया दुनिया के शीर्ष दस संसाधन संपन्न देशों में से एक है चीन के पूर्व खनिज संसाधनों पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए देश के साथ रणनीतिक सहयोग करना कोरिया गणराज्य के लिए अच्छा संकेत है।

इंडो-पैसिफ़िक रणनीति दस्तावेज़ "स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और समृद्ध इंडो-पैसिफ़िक" प्राप्त करने के लिए एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।[46] दस्तावेज़ रेखांकित करता है कि कोरिया गणराज्य मुख्य रूप से "स्वतंत्रता, लोकतंत्र, कानून के शासन और मानवाधिकारों" जैसे सार्वभौमिक मूल्यों पर स्थापित "अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को बनाए रखने और नियमों पर आधारित व्यवस्था को मजबूत करने" के माध्यम से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेगा।[47] एक विशिष्ट और स्पष्ट तरीके से कोरिया गणराज्य की इंडो-पैसिफ़िक रणनीति "एकतरफा स्थिति को बदलने के लिए बल या दबाव" के किसी भी कार्य को अस्वीकार करने के दृष्टिकोण पर जोर देती है।[48] इंडो-पैसिफ़िक दृष्टिकोण को लागू करने की प्रक्रिया में, यह कहा गया है कि कोरिया गणराज्य "सहयोग के तीन सिद्धांतों - समावेशिता, विश्वास और पारस्परिकता" पर आधारित कदम उठाएगा।[49] इसने जानबूझकर यह भी बताया है कि कोरिया गणराज्य की इंडो-पैसिफ़िक रणनीति "किसी विशिष्ट राष्ट्र को न तो लक्षित करेगी और न ही बाहर करेगी और आम हितों के लिए खुली रहेगी।"[50] यह विशेष मामला चीन की ओर निहित होगा, जिसके साथ कोरिया गणराज्य की स्थिति अभी भी जटिल है

45 Ankhtuya, 2022, "South Korea strengthens cooperation with Mongolia on mining", *NewsMN*, 2 September 2022, https://news.mn/en/797838/

46 *Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea*, 2022, "Strategy for a Free, Peaceful, and Prosperous Indo-Pacific Region", 28 December 2022, https://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5676/view.do?seq=322133&page=1

47 Ibid

48 Ibid

49 Ibid

50 Ibid

लेकिन दस्तावेज़ में कहा गया है कि "चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि और शांति प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख भागीदार है"।[51] कोरिया गणराज्य द्वारा अंततः "मुद्दों पर आधारित पारस्परिक समाधान" खोजने के लिए आर्थिक कूटनीति के माध्यम से चीन को शामिल करने का अपना प्रयास जारी रखने की संभावना है।[52]

एनएसपी और एनएसपी प्लस पर आधारित होते हुए, यून के प्रशासन ने आसियान के लिए एक विशेष क्षेत्रीय नीति के रूप में इंडो-पैसिफ़िक रणनीति के अधीन कोरिया-आसियान एकजुटता पहल (केएएसआई) की घोषणा की। इस पहल ने आसियान को "इंडो-पेसिफ़िकमें शांति और समृद्धि के निर्माण के लिए प्रमुख भागीदार" मानने पर सियोल की स्थिति को मजबूत किया है।[53] कोरिया गणराज्य ने "आसियान केंद्रीयता" और "आसियान आउटलुक ऑन द इंडो-पैसिफ़िक (एओआईपी)" के लिए अपने समर्थन पर भी जोर दिया है।[54]देश आसियान-कोरिया गणराज्य, मेकांग-कोरिया गणराज्य सहयोग निधि बढ़ाने की योजना बना रहा है जिसके परिणामस्वरूप आसियान की आवश्यकताओं को कोरिया गणराज्य की क्षमताओं के साथ समन्वयित किया जा सकेगा। दक्षिण एशिया क्षेत्र के संदर्भ में, कोरिया गणराज्य भारत को साझा मूल्यों के साथ एक अग्रणी क्षेत्रीय भागीदार के रूप में महत्व देता है। सियोल ने विदेशी मामलों और रक्षा पहलुओं में वरिष्ठ स्तर के परामर्श के माध्यम से नई दिल्ली के साथ रणनीतिक संचार और सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता भी निर्दिष्ट की है। ओशिनिया क्षेत्र के साथ, इंडो-पैसिफ़िक रणनीति दस्तावेज़ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सबसे महत्वपूर्ण रूप से प्रशांत द्वीप देशों (पीआईसी) के साथ संबंध बनाने के महत्व पर प्रकाश डालता है। कोरिया गणराज्य का जोर अब जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य देखभाल,

---

51 Ibid

52 Tunchinmang Langel, 2023, "Deconstructing Republic of Korea's (ROK) 'Strategy for a Free, Peaceful and Prosperous Indo-Pacific'", *Indian Council of World Affairs (ICWA)*, 31 January 2023, https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=8975&lid=5849

53 *Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea*, 2022, "Strategy for a Free, Peaceful, and Prosperous Indo-Pacific Region", 28 December 2022, https://www.mofa.go.kr/viewer/skin/doc.html?fn=20230106093833927.pdf&rs=/viewer/result/202301

54 *Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea*, 2022, "Strategy for a Free, Peaceful, and Prosperous Indo-Pacific Region", 28 December 2022, https://www.mofa.go.kr/viewer/skin/doc.html?fn=20230106093833927.pdf&rs=/viewer/result/202301

महासागरों और मत्स्य पालन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रशांत द्वीपों के सामने आने वाले मुद्दों को संबोधित करने पर केंद्रित हो रहा है। सियोल ने उल्लेख किया है कि वह "पार्टनर इन द ब्लू पैसिफ़िक (पीबीपी)" पहल के साथ-साथ "ब्लू पैसिफ़िक महाद्वीप के लिए 2050 रणनीति" का समर्थन करके पीआईसी को उनकी प्राथमिकताओं में समर्थन देना चाहता है। हिंद महासागर क्षेत्र के अफ्रीकी तट के संबंध में, सियोल अफ्रीका के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित देशों के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने के साथ-साथ प्रगाढ़ करने का इच्छुक है। इन संबंधों को मजबूत करने का प्राथमिक कारण इस तथ्य से लिया गया है कि कोरिया गणराज्य को प्राकृतिक गैस, कोयला, कच्चे तेल और अन्य खनिज संसाधन व्यापार की अपनी समुद्री शिपिंग खेप की सुरक्षा के लिए, हिंद महासागर क्षेत्र में अफ्रीका के पूर्वी तट पर लगातार उपस्थिति बनाए रखनी है। रणनीति दस्तावेज़ में घोषणा की गई है कि "कोरिया गणराज्य-अफ्रीका विशेष शिखर सम्मेलन" भी 2024 में निर्धारित किया जाएगा, जो अफ्रीकी देशों के साथ संबंधों के विस्तार पर सियोल के जोर को दर्शाता है।[55]

इंडो-पैसिफ़िक के लिए अपनी रणनीति के माध्यम से कोरिया गणराज्य इंडो-पेसिफ़िकके साथ-साथ विश्व स्तर पर बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों को खुले तौर पर पहचानने पर अपनी पिछली आपत्तियों को त्याग दिया है।

केवल आर्थिक पहलों पर ध्यान केंद्रित करने और बाहरी आक्रमणों के खिलाफ रक्षा के लिए अमेरिका पर अपनी पारंपरिक निर्भरता से हटने के साधन खोजने की कोशिश करने के बजाय, राष्ट्रपति यून की सरकार उत्तर कोरिया के लगातार उकसावे के साथ-साथ दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक प्रयासों के कारण और अधिक अस्थिर हुई जमीनी स्थिति का यथार्थवादी जायजा ले रही है।

55 Tunchinmang Langel, 2023, “Deconstructing Republic of Korea’s (ROK) ‘Strategy for a Free, Peaceful and Prosperous Indo-Pacific’ ”, *Indian Council of World Affairs (ICWA)*, 31 January 2023, https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=8975&lid=5849

केवल आर्थिक पहलों पर ध्यान केंद्रित करने और बाहरी आक्रमणों से बचाव के लिए अमेरिका पर अपनी पारंपरिक निर्भरता से हटने के साधन खोजने की कोशिश करने के बजाय, राष्ट्रपति यून की सरकार उत्तर कोरिया के लगातार उकसावे के साथ-साथ दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक प्रयासों के कारण और अधिक अस्थिर हुई जमीनी स्थिति का यथार्थवादी जायजा ले रही है। राष्ट्रपति यून की सरकार ने न केवल अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बढ़ाया है, यहां तक कि इसे "परमाणु-आधारित गठबंधन"[56] भी कहा है, बल्कि कोरिया गणराज्य ने जापान के साथ भी संबंधों को फिर से व्यवस्थित किया है, और यहां तक कि नाटो के साथ सहयोग को मजबूत और विस्तारित किया है।[57] राष्ट्रपति यून की सरकार "वैश्विक निर्णायक राज्य" जैसे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आर्थिक और सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले एक प्रमुख अभिनेता के रूप में अपनी तैयारी की वकालत कर रही है।इंडो-पैसिफ़िक महासागरों को सुरक्षित करने के आर्थिक और सुरक्षा प्रस्तावों को आधिकारिक तौर पर जोड़ने की क्षमता मून जे-इन प्रशासन की तुलना में कोरिया गणराज्य की विदेश नीति के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है।[58]

राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति

इंडो-पैसिफ़िक भू-रणनीतिक ढांचे की ओर कोरिया गणराज्य के संक्रमण को जब 7 जून 2023 को यूं सुक-येओल सरकार की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (एनएसएस) पेश की

56 Lee Haye-ah, 2023, “Yoon says alliance with U.S. upgraded to 'nuclear-based alliance' ”, *Yonhap News Agency*, 6 June 2023, https://en.yna.co.kr/view/AEN20230606001500315

57 *Office of the President of the Republic of Korea*, 2023, “'Tailored partnership' with NATO to boost security cooperation”, 12 July 2023, https://eng.president.go.kr/briefing/D8vhNAG5

58 Tunchinmang Langel, 2023, “Deconstructing Republic of Korea’s (ROK) ‘Strategy for a Free, Peaceful and Prosperous Indo-Pacific’ ”, *ICWA*, 31 January 2023, https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=8975&lid=5849

कोरिया गणराज्य का भारत-प्रशांत भू-रणनीतिक की ओर संक्रमण जब 7 जून 2023 को यूं सुक-येओल सरकार की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (एनएसएस) पेश की गई तो ढांचे को और बढ़ावा मिला।

गई तो इसे और बढ़ावा मिला।[59] पिछली सरकारों ने भी 2014 और 2018 में अपना एनएसएस जारी किया था। मून जे-इन सरकार ने शांतिपूर्ण और समृद्ध कोरियाई प्रायद्वीप के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2018 एनएसएस जारी किया था। इसकी तुलना में, राष्ट्रपति यूं सुक-येओल के अधीन 2023 एनएसएस मजबूत सुरक्षा द्वारा समर्थित कोरियाई प्रायद्वीप में स्थायी शांति को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। 2023 एनएसएस का आगमन राष्ट्रपति यून की सक्रिय पहुंच और कोरिया गणराज्य के "वैश्विक निर्णायक राज्य" विकसित करने के लिए उनकी नई इंडो-पैसिफ़िक रणनीति की वकालत की पृष्ठभूमि में हुआ। 2023 एनएसएस का उपशीर्षक "स्वतंत्रता, शांति और समृद्धि के लिए वैश्विक निर्णायक राज्य" के रूप में बताया गया है, जो राष्ट्रपति यून के दृष्टिकोण की भावनाओं को भी प्रतिध्वनित करता है। ऐसा कहा जाता है कि एनएसएस के दो संस्करण हैं, एक सार्वजनिक वितरण के लिए और दूसरा गोपनीय संस्करण है जो नीति कार्यान्वयन दिशानिर्देश के रूप में उपयोग के लिए प्रत्येक मंत्रालय को वितरित किया जाता है।[60] सार्वजनिक रूप से उपलब्ध संस्करण के संदर्भ में, एनएसएस निम्नलिखित तीन राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों या लक्ष्यों पर प्रकाश डालता है:

- सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्र की रक्षा करना

59 *Korea JoongAng Daily*, 2023, "Yoon government releases first security strategy paper", 7 June 2023, https://koreajoongangdaily.joins.com/2023/06/07/national/politics/Korea-National-Security-Strategy-Yoon-Suk-Yeol/20230607184116614.html

60 *Korea JoongAng Daily*, 2023, "Yoon government releases first security strategy paper", 7 June 2023, https://koreajoongangdaily.joins.com/2023/06/07/national/politics/Korea-National-Security-Strategy-Yoon-Suk-Yeol/20230607184116614.html

- कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति स्थापित करना और एकीकृत भविष्य के लिए तैयारी करना
- अपनी वैश्विक भूमिका का विस्तार करते हुए पूर्वी एशिया में समृद्धि के लिए जमीन तैयार करना

2023 एनएसएस को आठ खंडों में विभाजित किया गया है। एनएसएस समग्र रूप से समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का आकलन करता है और कोरिया गणराज्य के सुरक्षा वातावरण का मूल्यांकन प्रदान करता है। एनएसएस राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कोरिया गणराज्य की रणनीति और उद्देश्यों के सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है। यह कोरिया गणराज्य के लिए प्रमुख सुरक्षा चुनौतियों के रूप में निम्नलिखित को रेखांकित करता है:

- उत्तर कोरिया के सामूहिक विनाश के हथियार (डब्ल्यूएमडी) की धमकियाँ
- अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा
- आपूर्ति श्रृंखला संकट
- नए सुरक्षा ख़तरे (साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और संक्रामक रोग)

दस्तावेज़ के अनुसार, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उत्तर कोरिया की अपनी परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं की निरंतर प्रगति है, जो सामूहिक विनाश के हथियार (डब्ल्यूएमडी) हैं। उत्तर कोरिया से कैसे निपटा जाए यह पहेली कोरियाई युद्ध की समाप्ति के बाद से अस्तित्व के लिए ख़तरा बनी हुई है। 1953 में उत्तर और दक्षिण के बीच केवल एक युद्धविराम पर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन कोई औपचारिक शांति संधि स्थापित नहीं हुई, तब से दोनों कोरिया तकनीकी रूप से आमने-सामने हैं। दृष्टिकोणों में जो एकमात्र परिवर्तन देखा गया है वह इस बात पर है कि क्या तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाए या अधिक कट्टर दृष्टिकोण अपनाया जाए। कहा जाता है कि यूं सुक-येओल प्रशासन ने अपनी इंडो-पैसिफ़िक रणनीति और एनएसएस के माध्यम से मून जे-इन के

परमाणु और मिसाइल खतरों का मुकाबला करने के लिए, एनएसएस ने कोरिया गणराज्य, अमेरिका और जापान के बीच त्रिपक्षीय सुरक्षा सहयोग के महत्व को रेखांकित किया है।

अधीन पूर्व प्रशासन की विफलताओं से प्रेरणा ली है, जिसका उत्तर कोरिया के साथ तुष्टिकरण-आधारित दृष्टिकोण था।

दृष्टिकोण में परिवर्तन 2023 के एनएसएस के माध्यम से स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है। परमाणु और मिसाइल खतरों का मुकाबला करने के लिए, एनएसएस ने कोरिया गणराज्य, अमेरिका और जापान के बीच त्रिपक्षीय सुरक्षा सहयोग के महत्व को रेखांकित किया है। त्रिपक्षीय सुरक्षा सहयोग के अधीन 2022 से अगस्त 2023 तक तीनों देशों के नेताओं की चार बैठकें हो चुकी हैं। इसकी तुलना में, मून जे- 2017-2022 की अवधि में 6 जुलाई 2017को केवल एक राष्ट्राध्यक्षों का त्रिपक्षीय नेताओं का शिखर सम्मेलन देखा गया।[61] इसके अलावा, जापान के साथ हाल के अतीत के संबंधों को अलग करते हुए, एनएसएस के माध्यम से राष्ट्रपति यून के प्रशासन ने सियोल और टोक्यो के बीच संबंधों को एक दूरदर्शी, सहकारी साझेदारी में पुन: व्यवस्थित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

जैसा कि पहले कहा गया है, दोनों देश, कोरिया गणराज्य और जापान, इसलिए अब उत्तर कोरिया की बढ़ती परमाणु और मिसाइल क्षमताओं से ख़तरे के संबंध में आपसी सुरक्षा हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वर्ष 2023 में ही, कोरिया गणराज्य और जापान के दो नेताओं ने 18 अगस्त 2023 को कैंपडेविड समिट के मौके पर अपनी पांचवीं द्विपक्षीय बैठक के लिए मुलाकात की। टोक्यो, सियोल, हिरोशिमा और विनियस में उनकी पिछली बैठकों के बाद यह पांचवीं बैठक, मून

61 *Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2017*, "Japan-U.S.-ROK Trilateral Summit Meeting", 6 July 2017, https://www.mofa.go.jp/a_o/na/page3e_000703.html

62 *Ministry of Foreign Affairs of Japan*, 2023, "Japan-ROK Summit Meeting", 18 August 2023, https://www.mofa.go.jp/a_o/na/kr/page1e_000743.html

जे-इन युग की तुलना में राष्ट्रपति यून के दृष्टिकोण में गंभीरता और महत्वपूर्ण बदलाव को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त रूप से स्पष्ट है। एनएसएस में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी प्रकाश डाला गया है, जैसे अमेरिका-चीन के बीच बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण आर्थिक सुरक्षा पर तनाव बढ़ रहा है। दस्तावेज़ में नए उभरते सुरक्षा खतरों के रूप में उठाए गए अन्य गैर-पारंपरिक सुरक्षा मुद्दे थे जलवायु परिवर्तन, साइबर युद्ध, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान, और विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के कारण लगे वैश्विक झटकों के कारण बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा की आवश्यकता और यूक्रेन-रूस संकट।[63] इसके अलावा, फर्जी खबरों का प्रसार - गृह युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से लोगों के विस्थापन के कारण शरणार्थी संकट - ऐसा कहा जाता है कि इससे आतंकवाद और घृणा अपराधों के प्रसार में योगदान की बहस को बढ़ावा मिलता है।

एक अन्य क्षेत्र जिसे एक महत्वपूर्ण उभरते सुरक्षा ख़तरे के रूप में रेखांकित किया गया है वह है पर्यावरण विनाश का प्रभाव, जिसके कारण प्राकृतिक आपदाएं और भोजन की कमी होती है जिसके परिणामस्वरूप मानवता के अस्तित्व को ख़तरा पैदा होता है। नतीजतन, राजनीतिक और सुरक्षा ख़तरे वैश्विक आर्थिक अस्थिरता में योगदान दे रहे हैं और देश बढ़ते आर्थिक सुरक्षा जोखिमों के बीच संरक्षणवादी प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं। एनएसएस सुझाव देता है कि अलग-अलग देश इन खतरों से अकेले नहीं निपट सकते हैं और उनके प्रभाव को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस समय जमीनी स्थिति यह दर्शाती है कि कोरिया गणराज्य वास्तव में जापान के साथ मेल-मिलाप, कोरिया गणराज्य-यूएस गठबंधन को बढ़ाने और कोरिया गणराज्य-यूएस-जापान त्रिपक्षीय सुरक्षा सहयोग को संस्थागत बनाने के लिए कदम उठाकर एनएसएस के अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों तक पहुंच रहा है।

---

63 *Korea JoongAng Daily*, 2023, "Yoon government releases first security strategy paper", 7 June 2023, https://koreajoongangdaily.joins.com/2023/06/07/national/politics/Korea-National-Security-Strategy-Yoon-Suk-Yeol/20230607184116614.html

एनएसएस इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि 2020 के बाद से पिछले वर्षों में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस प्रकार उल्लेखनीय संकुचन हुआ है जिससे कमोडिटी की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक सुरक्षा वातावरण में तेजी से गिरावट आ रही है। रूस जैसे कुछ देशों पर ऊर्जा संसाधनों को हथियार बनाने, तेल की कीमतें बढ़ाने में योगदान देने का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि अन्य प्रमुख अनाज उत्पादक देश निर्यात नियंत्रण लागू कर रहे हैं, जिसने वैश्विक खाद्य संकट को बढ़ा दिया है। एनएसएस रिपोर्ट एक उभरते पैटर्न की ओर भी ध्यान आकर्षित करती है जहां आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से निपटने वाले देश आर्थिक गठबंधन बनाकर आत्मनिर्भरता की तलाश कर रहे हैं। इन रणनीतियों को अक्सर "रीशोरिंग" के रूप में जाना जाता है, जिसमें उत्पादन सुविधाओं को घरेलू बाजार में वापस स्थानांतरित करना, या "फ्रेंडशोरिंग" शामिल है। जिसमें उत्पादन सुविधाओं को सहयोगी देशों में स्थानांतरित करना शामिल है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए उत्पादन पर नियंत्रण पाने के लिए इन नीतियों का सक्रिय रूप से पालन किया जा रहा है। संरक्षणवादी प्रवृत्तियाँ वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं को मुक्त व्यापार से अपवर्जन प्रक्षेप पथ की ओर स्थानांतरित कर रही हैं। उन्नत प्रौद्योगिकी के मामले में, अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा ने दर्शाया है कि कैसे संरक्षणवादी प्रवृत्तियों ने असुविधाजनक रूप धारण कर लिया है। उन्नत प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ अधिकाधिक जुड़ती जा रही है, और देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। तकनीकी वर्चस्व पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा के साथ, एक अपरिहार्य संकट उभर रहा है जो आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर और बैटरी क्षेत्र को दोबारा आकार देने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसे परिदृश्य में, कोरिया गणराज्य ने अपने एनएसएस के माध्यम से सेमीकंडक्टर विनिर्माण और उन्नति के क्षेत्र में अमेरिका और जापान के साथ सहयोग करने का विचार सामने रखा है।

एक प्रमुख समुद्री रसद मार्ग के रूप में इंडो-पेसिफ़िक की महत्वपूर्ण स्थिति को पहचानते हुए, जिसमें वैश्विक आबादी का 65 प्रतिशत, विश्व सकल घरेलू उत्पाद का 62 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का 46 प्रतिशत शामिल है, सामरिक महत्व और सक्रिय
इंडो-पैसिफ़िक के साथ जुड़ाव को प्रमुखता से रेखांकित किया गया है।

सियोल, कोरिया गणराज्य-यूएस गठबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए मित्र राष्ट्रों के साथ आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को मजबूत करने की बढ़ती आवश्यकता को पहचानता है।

2023 के एनएसएस ने इंडो-पैसिफ़िक सुरक्षा वातावरण के महत्व पर भी जोर दिया है। इंडो-पैसिफ़िक भू-रणनीतिक निर्माण पर इस तरह का सक्रिय फोकस मून जे-इन के अधीन पूर्व प्रशासन में गायब था। दिसंबर 2022 में इंडो-पैसिफ़िक रणनीति दस्तावेज़ और जून 2023 में एनएसएस के प्रकाशन ने इस बारे में सभी आशंकाओं को दूर कर दिया है कि कोरिया गणराज्य खुद को इंडो-पैसिफ़िक का केंद्र मानता है या नहीं। राष्ट्रपति यून द्वारा वकालत किए गए यह कदम यह उसकी तुलना में एक आदर्श बदलाव है जब इंडो-पैसिफ़िक भू-रणनीतिक ढांचे की बात आती है तो राष्ट्रपति मून अनिच्छुक थे क्योंकि यह उनके दृष्टिकोण की स्वायत्तता से भटक गया था।

एक प्रमुख समुद्री रसद मार्ग के रूप में हिंद-प्रशांत की महत्वपूर्ण स्थिति को पहचानते हुए, जिसमें वैश्विक आबादी का 65 प्रतिशत, विश्व सकल घरेलू उत्पाद का 62 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का 46 प्रतिशत शामिल है इंडो-पैसिफ़िक के साथ रणनीतिक महत्व और सक्रिय जुड़ाव को प्रमुखता से रेखांकित किया गया है। हिंद-प्रशांत सुरक्षा माहौल को लेकर तीन प्राथमिक चिंताएं हैं। सबसे पहले, यह इंडो-पैसिफ़िक का बढ़ता भू-राजनीतिक महत्व है, जो अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। इस संदर्भ में,

एनएसएस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन का लक्ष्य आसियान के साथ अपने संबंधों का विस्तार करना और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को अपने हितों के अनुरूप आकार देने के अपने प्रयासों में तेजी लाना है, विशेष रूप से क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) जैसी पहल के माध्यम से। इसके उत्तर में, अमेरिका ने अपनी इंडो-पैसिफ़िक रणनीति पेश की है और समृद्धि के लिए इंडो-पैसिफ़िक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है अपने क्षेत्रीय साझेदारों और लोकतांत्रिक मूल्यों को साझा करने वाले देशों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना।

एनएसएस पाठ में यह भी उल्लेख किया गया है कि बढ़ते तनाव, विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में, ने अधिक सैन्य जोखिमों को जन्म दिया है, जिससे देशों को अपनी सुरक्षा रणनीतियों को तदनुसार अनुकूलित करने के लिए प्रेरित किया गया है। दूसरा, यह अमेरिका-चीन की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच हिंद-प्रशांत देशों के भीतर व्यावहारिक कूटनीति की बढ़ती खोज है। इस संदर्भ में, एनएसएस बताता है कि कैसे अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता केंद्रीय क्षेत्र के रूप में इंडो-पैसिफ़िक को प्रभावित कर रही है। परिणामस्वरूप, देश चाहे क्षेत्र के भीतर के हों या इसके बाहर के, उन्होंने अपनी-अपनी इंडो-पैसिफ़िक रणनीतियाँ पेश की हैं। ये रणनीतियाँ इंडो-पैसिफ़िक के महत्वपूर्ण महत्व को पहचानती हैं और इस क्षेत्र में उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ाने का लक्ष्य रखती हैं। ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण देते हुए, एनएसएस का कहना है कि देश अमेरिका के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए क्वाड और ऑकस जैसे लघुपक्षीय सहयोग अपना रहे हैं साथ ही समान लोकतांत्रिक सिद्धांतों को साझा करने वाले देशों के साथ अपने संबंधों को व्यापक बना रहे हैं। तीसरी प्राथमिक चिंता सहयोग की खोज में घटते प्रोत्साहन की है क्योंकि आर्थिक प्रतिस्पर्धा के कारण पूर्वोत्तर एशिया में संरक्षणवादी उपाय तेज हो गए हैं। विशेष रूप से, एनएसएस इस बात पर प्रकाश डालता है कि पूर्वोत्तर एशिया में,

एनएसएस पारंपरिक कोरिया गणराज्य सुरक्षा दुविधा, यानी, कोरियाई प्रायद्वीप पर अपना प्राथमिक ध्यान केंद्रित करने के लिए अच्छा काम करता है। यह उत्तर कोरिया के परमाणु ख़तरे, उत्तर कोरिया के लोगों के सामने बढ़ती आर्थिक कठिनाई और उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच गतिरोध के बीच पड़ोसी देशों के अपने प्रभाव को बढ़ाने के प्रयासों पर जोर देता है।

चीन, रूस और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ते तालमेल ने क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों, जैसे कि उत्तर कोरियाई परमाणु क्षमताओं के मुद्दे, को संबोधित करने के लिए आवश्यक सहयोगात्मक गति को नष्ट कर दिया है।

एनएसएस पारंपरिक कोरिया गणराज्य सुरक्षा दुविधा, यानी, कोरियाई प्रायद्वीप पर अपना प्राथमिक ध्यान केंद्रित करने के लिए अच्छा काम करता है। यह उत्तर कोरिया के परमाणु ख़तरे, उत्तर कोरिया के लोगों के सामने बढ़ती आर्थिक कठिनाई और उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच गतिरोध के बीच पड़ोसी देशों द्वारा अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रयासों पर जोर देता है। इसके अतिरिक्त, उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु क्षमताओं और नई मिसाइलों जैसे विभिन्न रणनीतिक और सामरिक हथियारों के चल रहे विकास पर जोर देकर, एनएसएस पड़ोसी देशों के लिए बढ़ते और महत्वपूर्ण ख़तरे पर प्रकाश डालता है। एनएसएस अभिनिर्धारित करता है कि परीक्षण के बहाने 2022 में 70 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रक्षेपण से पता चलता है कि प्योंगयांग शासन ने अपने निवासियों की आर्थिक कठिनाइयों पर रक्षा क्षमताओं को प्राथमिकता दी है, जो महामारी के कारण चल रहे प्रतिबंधों और रोकथाम उपायों के कारण और भी बदतर हो गया है।

कोरियाई प्रायद्वीप को घेरने वाली चार महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, जो क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण हितों के साथ विकसित हो रही भू-राजनीतिक गतिशीलता को ध्यान से देख रही हैं।

कोरिया गणराज्य के साथ गठबंधन में अमेरिका प्रतिबंधों और राजनयिक जुड़ावों के माध्यम से उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। जापान अमेरिका और कोरिया गणराज्य के साथ त्रिपक्षीय सुरक्षा सहयोग में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। हालाँकि, चीन और रूस, जो दोनों सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, कोरियाई प्रायद्वीप मुद्दे के राजनीतिक समाधान की ओर अधिक इच्छुक हैं, और दोनों देश प्योंगयांग के उकसावों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय समुदाय के प्रतिबंधों का विरोध करते हुए अपनी अलग-अलग राय व्यक्त करते हैं।

कोरिया गणराज्य की विदेश नीति में उत्तर कोरिया पहेली

कोरियाई विदेश नीति दृष्टिकोण के इतिहास में, कोरियाई प्रायद्वीप में उत्तर कोरिया की पहेली एक स्थायी समस्या बन गई है जिसे भूगोल के अभिशाप के कारण शायद ही कभी टाला जा सकता है। अब तक, दक्षिण कोरिया में लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली के माध्यम से कुल मिलाकर 20 राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, जबकि उत्तर कोरिया में 1948 से तीन सर्वोच्च नेता (किम इल-सुंग, किम जोंग-इल, किम जोंग उन) रहे हैं। दक्षिण में राष्ट्राध्यक्ष लगातार बदलते रहे हैं लेकिन उत्तर सियोल में प्रत्येक निर्वाचित प्रशासन के लिए एक जन्मजात बाधा बना हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न प्रशासनों के अधीन कार्रवाई और नीतियों के विभिन्न तरीके सामने आए। नतीजतन, जब उत्तर कोरिया के प्रति कूटनीति की बात आती है, मून जे-इन प्रशासन और यूं सुक-येओल प्रशासन के बीच तुलनात्मक विश्लेषण से दृष्टिकोण में अंतर का पता चलता है। यद्यपि दृष्टिकोण भिन्न हो सकता है, उद्देश्य मुख्य रूप से एक ही है, जो कोरियाई प्रायद्वीप का परमाणु निरस्त्रीकरण है।

अपने प्रशासन के दौरान, कोरियाई प्रायद्वीप पर मून जे-इन की नीति ने तीन लक्ष्यों को प्रतिध्वनित किया: शांति प्रथम, पारस्परिक सम्मान की भावना और खुली नीति।

मून जे-इन और उत्तर कोरिया

10 मई 2017 को अपने उद्घाटन के बाद मून जे-इन ने तुरंत उत्तर कोरिया के साथ बातचीत और शांति की अपील की। उनकी अपील अनसुनी कर दी गई क्योंकि उत्तर कोरिया ने 15 राउंड बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया, 3 सितंबर 2017 को परमाणु परीक्षण किया, **64** और 29 नवंबर 2017 को ह्वासोंग-15 ICBM लॉन्च किया।**65** प्योंगयांग के अड़ियल व्यवहार के बावजूद, मून जे-इन प्रशासन ने 7 जुलाई 2017 को "कोरियाई प्रायद्वीप शांति पहल" की घोषणा की। इसका उद्देश्य शांतिपूर्ण एकीकरण के लिए अंतर-कोरियाई संबंधों को फिर से स्थापित करने की दिशा में एक नीतिगत निर्देश था। अपने प्रशासन के दौरान, कोरियाई प्रायद्वीप पर मून जे-इन की नीति ने तीन लक्ष्यों को प्रतिध्वनित किया: शांति प्रथम, पारस्परिक सम्मान की भावना और खुली नीति।**66** "पीस फ़र्स्ट" नीति को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ-साथ समृद्धि की नींव के रूप में बरकरार रखा गया था। "परस्पर सम्मान की भावना" में, कोरिया गणराज्य ने "3 नंबर" की वकालत की, यानी, उत्तर के पतन की कोई इच्छा नहीं, अवशोषण द्वारा एकीकरण की कोई खोज नहीं, और कृत्रिम साधनों के माध्यम से एकीकरण की कोई खोज नहीं।

64 *CTBTO*, 2017, "September 2017 DPRK Nuclear Test", 3 September 2017, https://www.ctbto.org/our-work/detecting-nuclear-tests/2017-dprk-nuclear-test

65 *Missile Defense Advocacy Alliance*, 2023, "Hwasong-15/KN-22", February 2023, https://missiledefenseadvocacy.org/missile-threat-and-proliferation/todays-missile-threat/north-korea/hwasong-15/

66 *Ministry of Unification*, *Republic of Korea*, n.d., "Three Goals", https://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/policylssues/koreanpeninsula/goals/

मून जे-इन ने बातचीत पर केंद्रित नीति के साथ कोरियाई प्रायद्वीप में शांति और समृद्धि के निर्माण पर दृढ़ता से काम किया, जो उत्तर कोरिया के मुद्दों पर कोरिया गणराज्य में प्रगतिशील सरकारों का मानक तरीका था।

"खुली नीति" सार्वजनिक भागीदारी और बातचीत को आमंत्रित करने के लिए थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नीति को लोगों द्वारा पूरी तरह से समझा गया है - और उनके द्वारा बनाया गया है।

मून जे-इन ने नीति-केंद्रित संवाद के साथ कोरियाई प्रायद्वीप में शांति और समृद्धि के निर्माण के लिए दृढ़ता से प्रयास किया, जो उत्तर कोरिया के मुद्दों पर कोरिया गणराज्य की प्रगतिशील सरकारों की मानक कार्यप्रणाली थी। दक्षिण कोरिया में 2018 प्योंगचांग शीतकालीन खेलों का लाभ प्योंगयांग को वार्ता में प्रवेश के लिए एक प्रलोभन के रूप में दिया गया था। अप्रैल 2018 में पनमुनजोम में इंटर-कोरियाई हाउस ऑफ़ फ्रीडम में ऐतिहासिक अंतर-कोरियाई शिखर सम्मेलन भी हुआ था। इसके बाद, जून 2018 में ट्रम्प और किम जोंग उन के बीच सिंगापुर में बैठक हुई। राष्ट्रपति मून 2017 में पदभार संभालने के बाद तीसरी अंतर-कोरियाई शिखर बैठक आयोजित करने के लिए सितंबर 2018 में प्योंगयांग भी गए थे। अंततः, उत्तर कोरिया-संयुक्त राज्य अमेरिका हनोई शिखर सम्मेलन 2019 में आयोजित किया गया, जो एक विभक्ति बिंदु बन गया, भले ही मून जे-इन इसे एक प्रगतिशील मील के पत्थर के रूप में चित्रित करना चाहते थे जो उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण की ओर ले जाएगा। प्योंगयांग द्वारा परमाणु निरस्त्रीकरण पर अपना रुख बदलने से कोई ठोस प्रगति हासिल नहीं हुई और अंतर-कोरियाई संबंध। उत्तर कोरिया ने आगे किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया और इसके बजाय परीक्षण की आड़ में बैलिस्टिक मिसाइलों की लगातार गोलीबारी शुरू कर दी।

कुल मिलाकर, उत्तर कोरिया के संबंध में मून जे-इन के नीतिगत दृष्टिकोण ने किसी भी पूर्व-निवारक या निवारक सैन्य कार्रवाई का विरोध किया। सियोल ने यहां तक घोषित कर दिया कि उसके पास अपना कोई परमाणु हथियार नहीं होगा। इसके अलावा, मून जे-इन ने कहा कि कोरिया गणराज्य ने उत्तर में शासन परिवर्तन की मांग नहीं की और साथ ही केवल दक्षिण कोरियाई शर्तों के अनुसार अवशोषण द्वारा कोई बलपूर्वक एकीकरण नहीं किया। मून जे-इन प्रशासन ने एनएसपी और एनएसपी प्लस भी लॉन्च किया था, जिसमें सियोल ने "शांति" और "समृद्धि" स्तंभ के माध्यम से उत्तर कोरिया की समस्या को संबोधित किया। एनएसपी के माध्यम से मून जे-इन ने पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण, कोरियाई प्रायद्वीप पर स्थायी शांति और अंतर-कोरियाई संबंधों को बेहतर बनाने में मदद के लिए एक तटस्थ भागीदार के रूप में आसियान की सहायता भी मांगी।

यूं सुक-योल और उत्तर कोरिया

दूसरी ओर, राष्ट्रपति यून सुक-योल ने उत्तर कोरिया के प्रति अधिक कठोर रुख अपनाया। प्रशासन की कमान प्रगतिशील खेमे से रूढ़िवादी खेमे में स्थानांतरित होने के साथ, उत्तर कोरिया की पहेली को अब वैचारिक स्पेक्ट्रम के बिल्कुल अलग सिरे पर निपटाया जा रहा है। राष्ट्रपति यूं सुक-योल ने कोरिया गणराज्य की वायु और मिसाइल रक्षा को मजबूत करने, उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु और मिसाइल खतरों को बेअसर करने के लिए वाशिंगटन की विस्तारित प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने और समन्वित क्षमताओं और सहयोग को बढ़ाने के लिए कोरिया गणराज्य, अमेरिका और जापान के बीच बहु-डोमेन त्रिपक्षीय सुरक्षा सहयोग को संचालित करने की घोषणा की है। उनकी प्राथमिकता शांति की दिशा में पहले कदम के रूप में उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण को आगे बढ़ाना है

जो कोरिया गणराज्य को एक "वैश्विक निर्णायक राज्य" में बदल देगा जो स्वतंत्रता, शांति और समृद्धि को आगे बढ़ाएगा।[67]

मून जे-इन की तुलना में राष्ट्रपति यून उत्तर कोरिया से कैसे संपर्क कर रहे हैं, इसमें पहले से ही स्पष्ट अंतर है। उत्तर कोरिया के प्रति अपने कट्टरपंथी दृष्टिकोण की खोज में, राष्ट्रपति यून ने उत्तर कोरिया के उकसावे या आपसी ख़तरे पर जापान के साथ अपने सुरक्षा हितों को मिलाने के लिए एक व्यावहारिक भविष्य-उन्मुख दृष्टिकोण भी अपनाया है। उत्तर कोरियाई ख़तरा एक आपसी चिंता के रूप में बना हुआ है, लेकिन ऐतिहासिक, राजनीतिक और व्यापारिक असहमति ने सियोल और टोक्यो को अतीत में इसे सक्रिय रूप से संबोधित करने में बाधा उत्पन्न की है। दरअसल, मून जे-इन और शिंजो आबे के कार्यकाल के दौरान, उनके द्विपक्षीय संबंधों का सबसे कठिन चरण तब आया जब दक्षिण कोरियाई सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जापानी कंपनियों के खिलाफ युद्धकालीन श्रम मुआवजे के दावों के पक्ष में फैसला सुनाया।[68] हालाँकि, राष्ट्रपति यून के चुनाव के बाद, उनके रिश्ते को फिर से स्थापित करने और सहयोग के एक नए युग की शुरुआत के प्रतीक के रूप में, 12 वर्षों में पहला जापान-कोरिया गणराज्य शिखर सम्मेलन 16 मार्च 2023 को टोक्यो, जापान में हुआ।[69]

यूं सुक-योल प्रशासन का प्राथमिक उद्देश्य उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण को प्राप्त करने और फिर बदले में आर्थिक रियायतें प्रदान करने पर केंद्रित है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक-योल ने भी उत्तर कोरिया के

67 Yoon Suk-yeol, 2022, "South Korea Needs to Step Up", *Foreign Affairs*, 8 February 2022, https://www.foreignaffairs.com/articles/south-korea/2022-02-08/south-korea-needs-step

68 Choe Sang-hun, "South Korean Court Orders Mitsubishi of Japan to Pay for Forced Wartime Labor", *The New York Times*, 29 November 2018, https://www.nytimes.com/2018/11/29/world/asia/south-korea-wartime-compensation-japan.html

69 *Ministry of Foreign Affairs of Japan*, 2023, "Japan-ROK Summit Meeting", 16 March 2023, https://www.mofa.go.jp/a_o/na/kr/page1e_000593.html

यूं सुक-येओल प्रशासन का प्राथमिक उद्देश्य उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण और फिर बदले में आर्थिक रियायतें प्रदान करने पर केंद्रित है।

उकसावे की स्थिति में "पूर्व-निवारक हमले" की संभावना का संकेत दिया था, खासकर अगर इसमें परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइल शामिल हो।[70] 4 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान, यून सुक-येओल प्रशासन ने उत्तर कोरिया के किसी भी भविष्य के उकसावे के लिए मजबूत जवाबी कार्रवाई के साथ जवाब देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की थी।[71] जिन जवाबी उपायों पर विचार किया जा रहा है उनमें से एक है "थ्री एक्सिस-डिफेंस सिस्टम" का कार्यान्वयन[72] या "त्रिस्तरीय रक्षा प्रणाली।"[73] इस प्रणाली में एक "रणनीतिक कमांड" की सुविधा होने की उम्मीद है, जो "तीन-अक्ष" रक्षा प्रणाली के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। इस प्रणाली का उद्देश्य उत्तर कोरिया की बढ़ती परमाणु और मिसाइल क्षमताओं से उत्पन्न खतरों का मुकाबला करना है। शब्द "थ्री-एक्सिस" मुख्य रूप से उत्तर कोरिया के खिलाफ दक्षिण कोरिया की सैन्य कार्रवाई के तीन अलग-अलग चरणों से मेल खाता है। प्रारंभिक चरण में किल चेन प्री-एम्प्टिव स्ट्राइक प्लेटफ़ॉर्म शामिल है।

70 *Hankyoreh*, 2022, "Yoon says preemptive strike is only answer to N. Korea's hypersonic missiles", 12 January 2022, https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/1027059.html

71 *The Korea Times*, 2022, "Escalating tensions on peninsula", 7 October 2022, https://www.koreatimes.co.kr/www/opinon/2022/10/202_337484.html

72 *The Korea Times*, 2022, "South Korea to create 'strategic command' to lead 'three-axis' system against North Korea's threats", 6 July 2022, https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2022/07/103_332275.html

73 *HANKYOREH*, 2016, "South Korea announces 'Massive Punishment and Retaliation' in response to fifth nuke test", 13 September 2016, https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_northkorea/761301.html

उत्तर कोरियाई ख़तरे के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रपति यून अपने नीतिगत दृष्टिकोण की केंद्रीय धुरी के रूप में वाशिंगटन के साथ गहरा गठबंधन बनाने के लिए एक सक्रिय विदेशी कूटनीति मार्ग भी अपना रहे हैं।

इसमें "कोरिया मैसिव पनिशमेंट एंड रिटालिएशन" योजना के माध्यम से उत्तर कोरिया के नेतृत्व को बेअसर करने के लिए डिज़ाइन की गई एक परिचालन रणनीति शामिल है।[74] दक्षिण कोरियाई सशस्त्र बलों ने 17 से 28 अक्टूबर 2022 तक चलने वाला अपना वार्षिक 12-दिवसीय होगुक फ़ील्ड प्रशिक्षण अभ्यास भी आयोजित किया।[75] फिर भी, प्योंगयांग अभी भी सामरिक परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता के साथ अधिक मिसाइल परीक्षण करने के बहाने होगुक अभ्यास जैसे सैन्य अभ्यासों का उपयोग करता है। दक्षिण कोरिया के कट्टरपंथी रुख के जवाब में उत्तर कोरिया द्वारा अपना सातवां परमाणु परीक्षण करने की भी अटकलें लगाई गई हैं।

उत्तर कोरियाई ख़तरे के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रपति यून अपने नीति दृष्टिकोण की केंद्रीय धुरी के रूप में वाशिंगटन के साथ गहरा गठबंधन बनाने के लिए एक सक्रिय विदेशी कूटनीति मार्ग भी अपना रहे हैं। 26अप्रैल2023 को हस्ताक्षरित वाशिंगटन घोषणा का हवाला देते हुए।[76] राष्ट्रपति यून ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने गठबंधन के उन्नयन की घोषणा की।

74 *HANKYOREH*, 2016, "South Korea announces 'Massive Punishment and Retaliation' in response to fifth nuke test", 13 September 2016, https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_northkorea/761301.html

75 Ji Da-gyum, "S. Korea begins major Hoguk field training exercise amid N. Korea's saber-rattling", *Korea Herald*, 17 October 2022, https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20221017000637

76 *The White House*, 2023, "Washington Declaration", 26 April 2023, https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/04/26/washington-declaration-2/

इस उन्नयन को सियोल-वाशिंगटन संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा सकता है, जिसे अब राष्ट्रपति यून ने "परमाणु-आधारित गठबंधन" के रूप में घोषित किया है।"[77] अगस्त 2023 में, दक्षिण कोरिया ने अमेरिका के साथ "उलची फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज" का भी आयोजन किया, जिसे वर्षों में उसके सबसे बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यासों में से एक माना जाता है, जिसमें संपूर्ण युद्ध परिदृश्य पर आधारित लगभग 30 प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल थे।[78] संदर्भ के लिए, यह याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि सिंगापुर शिखर सम्मेलन में अमेरिका और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ़ कोरिया (डीपीआरके) के बीच बातचीत के कारण 2018 में वार्षिक उल्ची स्वतंत्रता अभ्यास को निलंबित कर दिया गया था।[79] ये वार्ता उत्तर कोरिया के प्रति राष्ट्रपति मून की "पीस फ़र्स्ट" नीति की भव्य योजना का हिस्सा थी। हालाँकि, इसे 2018 के अंत से बहुत छोटे पैमाने पर पुनर्गठित किया गया था, लेकिन 2022 में मून जे-इन के कार्यकाल के अंत तक एक संक्षिप्त संस्करण के रूप में जारी रहा। 2021 में उल्ची फ्रीडम अभ्यास वास्तव में एक कंप्यूटर-सिम्युलेटेड प्रारूप में आयोजित किया गया था, जिसमें कोई फील्ड अभ्यास और लाइव-फायर अभ्यास नहीं था।[80] यह केवल 2022 में था कि राष्ट्रपति यून के चुनाव जीतने के बाद कोरिया गणराज्य ने एक बार फिर अमेरिका के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास को फिर से शुरू किया। एनएसएस2023 के माध्यम से कोरिया गणराज्य-यूएस संयुक्त अभ्यास और प्रशिक्षण की बहाली और विस्तार की भी स्पष्ट रूप से वकालत की गई थी।. इसके परिणाम जमीन पर अभ्यास के माध्यम से देखे जा सकते हैं क्योंकि कोरिया गणराज्य ने अगस्त 2022 और अगस्त 2023 में

77 *The Korea Times*, 2023, "Yoon says alliance with US upgraded to 'nuclear-based alliance' ", 6 June 2023, https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2023/06/113_352404.html

78 *Nikkei Asia*, 2023, "South Korea, U.S. begin military drills amid North Korea threat", 21 August 2023, https://asia.nikkei.com/Politics/Defense/South-Korea-U.S.-begin-military-drills-amid-North-Korea-threat

79 *U.S Department of Defense*, 2018, "DoD Indefinitely Suspends Ulchi Freedom Guardian, Other Exercises", June 22, 2018, https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/1558409/dod-indefinitely-suspends-ulchi-freedom-guardian-other-exercises/

80 Oh Seok-min, 2021, "USFK commander calls for more achievements after summertime Korea-U.S. exercise", *Yonhap News Agency*, 2 September 2021, https://en.yna.co.kr/view/AEN20210902005300325

उल्ची फ्रीडम एक्सरसाइज के माध्यम से अमेरिका के साथ अपने सबसे बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास को पुनर्जीवित किया।

जून 2023 में कोरिया गणराज्य द्वारा प्रकाशित एनएसएस ने विदेशी कूटनीति के प्रति सियोल के दृष्टिकोण में एक और अध्याय खोला, जो न केवल प्योंगयांग के उकसावों के संबंध में कोरिया गणराज्य के आसपास के जटिल सुरक्षा माहौल से निपटने में स्पष्टता और साहस को दर्शाता है लेकिन भू-राजनीति में प्रवाह को भी संबोधित करता है और एक ब्लूप्रिंट प्रदान करता है कि कैसे कोरिया गणराज्य एक "वैश्विक निर्णायक राज्य" बनने का लक्ष्य बना रहा है, जो इंडो पैसिफ़िक का केंद्र है। कोरिया गणराज्य ने राष्ट्रपति यून के अधीन दिखाया है कि सुरक्षा खतरों के सभी संभावित परिदृश्यों का सक्रिय रूप से जवाब देने के लिए देश की क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए उपाय करने में संकोच नहीं किया जाएगा।

2. कोरिया गणराज्य की विदेश नीति कूटनीति का संदर्भ: मध्य शक्ति से वैश्विक निर्णायक राज्य तक

कोरिया गणराज्य या दक्षिण कोरिया को एक दशक से भी अधिक समय से विदेश नीति पर अपनी रूपरेखा के लिए "मध्यम शक्ति" कहा जाता है। हालाँकि, संदर्भ और नीति-निर्माताओं के दृष्टिकोण के आधार पर इस शब्द के अलग-अलग अर्थ और निहितार्थ हैं। "मध्यम शक्ति" की परिभाषा और अनुप्रयोग को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भूगोल, पदानुक्रम, रणनीति, ऐतिहासिक स्मृति, बजटीय बाधाएं, क्षेत्रीयकरण और आर्थिक विकास हैं।

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक-योल ने "वैश्विक निर्णायक राज्य" (जीपीएस) बनने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण व्यक्त किया है और वैश्विक नेतृत्व का पद संभालने के प्रति अपने समर्पण का संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय की अपील के अनुरूप, दक्षिण

राष्ट्रपति यून ने भी जापान के साथ भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण अपनाया है, भले ही ऐतिहासिक असहमति अभी भी स्थानीय आबादी की यादों में बनी हुई है कोरिया गणराज्य का, जो अक्सर टोक्यो के साथ अंतराल को पाटने में किसी भी सरकार के लिए घरेलू जोखिम के रूप में कार्य करता है।

कोरिया अपनी स्थिति के अनुरूप अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस भूमिका में वैश्विक स्तर पर स्वतंत्रता, उदार लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे सिद्धांतों को साझा करना और उनकी सुरक्षा करना शामिल है। कोरिया गणराज्य-यूएस गठबंधन को 2022 में "कोरियाई प्रायद्वीप से परे वैश्विक व्यापक रणनीतिक गठबंधन" में भी अपग्रेड किया गया था। अप्रैल 2023 में जारी वाशिंगटन घोषणा के आधार पर, राष्ट्रपति यूं सुक-योल ने यहां तक दावा किया है कि कोरिया-अमेरिका गठबंधन अब "परमाणु-आधारित गठबंधन" में अपग्रेड हो गया है।[81] राष्ट्रपति यून ने भी जापान के साथ भविष्य-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाया है, भले ही ऐतिहासिक असहमति अभी भी कोरिया गणराज्य की स्थानीय आबादी की यादों में बनी हुई है जो अक्सर टोक्यो के साथ अंतराल पाटने वाली किसी भी सरकार के लिए घरेलू जोखिम के रूप में काम करती है।

कोरिया गणराज्य की मध्य शक्ति स्थिति और "वैश्विक निर्णायक राज्य" बनने की इसकी नई आकांक्षाओं के बीच अंतर को इस प्रकार देखा जा सकता है:

- कोरिया गणराज्य की मध्य शक्ति स्थिति अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में इसकी सापेक्ष स्थिति और क्षमताओं पर आधारित है, जबकि वैश्विक निर्णायक राज्य का दृष्टिकोण इसकी सक्रिय भूमिका और वैश्विक शासन में योगदान पर आधारित है।

81 Lee Haye-ah, 2023, "Yoon says alliance with U.S. upgraded to 'nuclear-based alliance' ", *Yonhap News Agency*, 6 June 2023, https://en.yna.co.kr/view/AEN20230606001500315

- कोरिया गणराज्य की मध्य शक्ति की स्थिति अक्सर इसकी क्षेत्रीय गतिशीलता और सुरक्षा चुनौतियों से बाधित होती है, खासकर उत्तर कोरिया, चीन और जापान के संबंध में, जबकि ग्लोबल पिवोटल स्टेट विज़न का उद्देश्य अपने राजनयिक क्षितिज और साझेदारी को अपने निकटतम पड़ोस से परे विस्तारित करना है।
- कोरिया गणराज्य की मध्य शक्ति की स्थिति घरेलू राजनीति और विभिन्न प्रशासनों की प्राथमिकताओं के आधार पर परिवर्तन और असंगतता के अधीन है, जबकि ग्लोबल पिवोटल स्टेट विज़न का उद्देश्य एक दीर्घकालिक और सुसंगत रणनीति है जो पक्षपातपूर्ण मतभेदों से परे है।

मुख्य रूप से, मून जे-इन के अधीन कोरिया गणराज्य, जिसकी नीति कोरियाई प्रायद्वीप में शांति लाने और एकीकरण करने के लिए बातचीत पर केंद्रित थी, उत्तर कोरिया के अस्तित्व संबंधी ख़तरे से निपटने के दौरान एक स्वायत्त मध्य शक्ति के रूप में अपनी भूमिका को अपनाने में असमर्थ था। जबकि मून जे-इन के अधीन कोरिया गणराज्य ने खुद को केवल उत्तर कोरिया के क्षेत्रीय आधिपत्यों और कार्यों से बांध रखा था,[82] उसे अमेरिका के साथ अपने गठबंधन, चीन के साथ अपनी आर्थिक परस्पर निर्भरता, जापान के साथ अपने ऐतिहासिक विवादों और उत्तर कोरिया के साथ अपनी सुरक्षा दुविधा को भी संतुलित करना था। मून जे-इन द्वारा एक राजनयिक उपकरण के रूप में प्रख्यापित एनएसपी बदलती अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में कोरिया गणराज्य की सापेक्ष स्थिति और क्षमताओं को पेश करने के लिए असंगत था। दूसरी ओर, राष्ट्रपति यून के "वैश्विक निर्णायक राज्य" के दृष्टिकोण वैश्विक नेतृत्व और वैश्विक शासन के लिए कोरिया गणराज्य की आकांक्षाओं की पूर्ति में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है। कोरिया गणराज्य अब प्रतिबंधित नहीं है, बल्कि अपने राजनयिक क्षितिज और साझेदारियों का विस्तार व्यापक हिंद-प्रशांत की ओर कर रहा है।

82 Iain Watson, 2020, "South Korea's changing middle power identities as response to North Korea", The Pacific Review, 33:1, 1-31, DOI: 10.1080/09512748.2018.1518923

ग्लोबल पिवोटल स्टेट विज़न राष्ट्रपति मून के अधीन कोरिया गणराज्य की पिछली कूटनीति से आवश्यक परिवर्तन का एक स्पष्ट संकेत है जो कि भू-राजनीति में एक मध्य शक्ति के रूप में इसकी सापेक्ष स्थिति के साथ असंगत थे। सियोल अब भविष्य-उन्मुख दृष्टिकोण की राह पर है जो दीर्घकालिक और घरेलू राजनीति से आगे निकलने के लिए पर्याप्त सुसंगत है।

वर्तमान रणनीतिक विकल्पों और अपनाने के दृष्टिकोण को आकार देने वाले कारक

इस शोध पत्र के विश्लेषण के अनुसार, वर्तमान भू-राजनीति में, कोरिया गणराज्य की विदेश नीति कूटनीति के संदर्भ का विश्लेषण तीन दृष्टिकोणों से किया जा सकता है: भू-राजनीतिक वातावरण, सापेक्ष क्षमता और घरेलू राजनीति। सबसे पहले, भूराजनीतिक वातावरण उन बाहरी स्थितियों और बाधाओं को संदर्भित करता है जो कोरिया गणराज्य की विदेश नीति के विकल्पों और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। कोरिया गणराज्य एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां चार प्रमुख शक्तियां (अमेरिका, चीन, रूस और जापान) प्रभाव और हितों के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं, और जहां परमाणु-सशस्त्र उत्तर कोरिया इसकी सुरक्षा और स्थिरता के लिए लगातार ख़तरा बना हुआ है। इसलिए, उसे अपनी संप्रभुता, स्वायत्तता और पहचान बनाए रखते हुए इस जटिल और गतिशील वातावरण से निपटना होगा।

दूसरा, सापेक्ष क्षमता आंतरिक संसाधनों और क्षमताओं को संदर्भित करती है जो कोरिया गणराज्य की विदेश नीति की कार्रवाइयों और उपलब्धियों को सक्षम बनाती है। देश ने स्वयं को एक युद्धग्रस्त और गरीब देश से एक मजबूत अर्थव्यवस्था, एक सक्षम सेना और एक जीवंत नागरिक समाज के साथ एक समृद्ध और लोकतांत्रिक राष्ट्र में बदल दिया है। कोरिया गणराज्य ने अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा और प्रभाव को बढ़ाने के लिए अपनी संस्कृति, प्रौद्योगिकी और कूटनीति जैसी नरम शक्ति भी विकसित की है।

कोरिया गणराज्य ने अपने राष्ट्रीय हितों और मूल्यों को आगे बढ़ाने के साथ-साथ वैश्विक शासन और विकास में योगदान देने के लिए अपनी सापेक्ष क्षमता का लाभ उठाया है। वर्तमान समय में, कोरिया गणराज्य भी अपनी रणनीतिक अस्पष्टता को त्यागने के चरण में है, अपनी मध्य शक्ति की स्थिति से अपनी सैन्य क्षमताओं के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा मुद्दों के समाधान के लिए सैन्य गठबंधन के प्रति आश्वस्त एक संक्रमणकालीन स्थिति में विकसित हो रहा है।

तीसरे, घरेलू राजनीति उन आंतरिक कारकों और अभिनेताओं को संदर्भित करती है जो कोरिया गणराज्य की विदेश नीति प्राथमिकताओं और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। कोरिया गणराज्य एक बहुलवादी लोकतंत्र है, जहां विभिन्न राजनीतिक दल, हित समूह, मीडिया आउटलेट और जनता की राय सत्ता और प्रतिनिधित्व के लिए प्रतिस्पर्धा करती है। कोरिया गणराज्य की विदेश नीति चुनावी चक्रों, नीतिगत बहसों, सामाजिक आंदोलनों और जनता की भावनाओं के अधीन है। कोरिया गणराज्य की विदेश नीति भी इसकी ऐतिहासिक स्मृति, राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक मूल्यों से आकार लेती है। जापान-कोरिया गणराज्य ऐतिहासिक विवाद, विशेष रूप से घरेलू आबादी की याद में, टोक्यो के साथ अंतराल को पाटने में किसी भी सरकार के लिए लगातार बाधा बने रहे हैं।

कोरिया गणराज्य की विदेश नीति कूटनीति के इस संदर्भ को देखते हुए, इस अध्ययन का विश्लेषण स्कॉट ए.स्नाइडर(2018) के तर्क का अच्छी तरह से समर्थन पाता है कि सियोल दो अक्षों के बीच झूल रहा है: बाहरी अभिविन्यास बनाम आंतरिक अभिविन्यास, और गठबंधन बनाम स्वायत्तता।[83] हालाँकि, इस शोध के अनुसार, उन दो अक्षों का विलय हो रहा है जिनका सियोल अनुसरण कर रहा है। एक महत्वपूर्ण सकारात्मक सहसंबंध देखा गया है जहां राष्ट्रपति मून के नीतिगत दृष्टिकोण को स्वायत्तता के मंच पर आंतरिक अभिविन्यास के साथ जोड़ा जा सकता है,

83 Scott A. Snyder, 2018, *South Korea at the Crossroads: Autonomy and Alliance in an Era of Rival Powers*, Columbia University Press, https://doi.org/10.7312/snyd18548

हालाँकि राष्ट्रपति यून अपनी नीति के आधार के रूप में गठबंधनों के साथ बाह्योन्मुख होने के अपने दृष्टिकोण में स्पष्टवादी थे।

गठबंधन और स्वायत्तता के संदर्भ में, चार दृष्टिकोण बताए गए हैं: "संकीर्ण गठबंधन निर्भरता, गठबंधन-सक्षम अंतर्राष्ट्रीयतावाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद प्लस स्वायत्तता, और तटस्थता के माध्यम से स्वतंत्रता"।[84] अध्ययन ने संकेत दिया है कि उल्लिखित दृष्टिकोण 2017 से सियोल सरकार के साथ एक संबंध दिखाते हैं। ग्राफ़ 1 मून जे-इन से यूं सुक-योल के कार्यकाल तक कोरिया गणराज्य की विदेश नीति के दृष्टिकोण के राजनीतिक स्पेक्ट्रम को दर्शाता है। ग्राफ़ तालिका 1 में दिए गए सारणीबद्ध अंकों के माध्यम से तैयार किया गया है, जो इस शोध पत्र के विश्लेषण के अनुसार है। 1 से 10 के पैमाने पर, 0 का स्कोर यह दर्शाता है कि संबंधित सरकारी नीति का उल्लिखित दृष्टिकोण के साथ कोई संबंध नहीं था। 5 का स्कोर यह दर्शाता है कि सरकार की नीति के टुकड़े उल्लिखित दृष्टिकोण से मेल खाते हैं लेकिन शर्तों के साथ। 10 का स्कोर सकारात्मक सहसंबंध दिखाने के लिए है।

तटस्थता के माध्यम से स्वतंत्रता एक ऐसा दृष्टिकोण है जो कोरिया गणराज्य की आत्मनिर्भरता या तटस्थता की मांग करते हुए अन्य क्षेत्रीय या वैश्विक गठबंधन के पक्ष में अमेरिका के साथ गठबंधन को कम करता है या छोड़ देता है। यह दृष्टिकोण एक आंतरिक अभिविन्यास को दर्शाता है जो कोरिया गणराज्य की संप्रभुता या पहचान पर जोर देता है, साथ ही स्वायत्तता को अधिकतम करता है जो अमेरिकी प्रभाव या हस्तक्षेप को चुनौती देता है या अस्वीकार करता है। इस अध्ययन के माध्यम से, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मून जे-इन प्रशासन (2017- 2022) तटस्थता दृष्टिकोण के माध्यम से स्वतंत्रता में फिट होगा। यह विश्लेषण दृष्टिकोणों की समझ के माध्यम से आता है

84 Ibid

तालिका 1

राष्ट्रपति	संकीर्ण गठबंधन निर्भरता	गठबंधन-सक्षम अंतर्राष्ट्रीयवाद	तटस्थता के माध्यम से स्वतंत्रता	अंतर्राष्ट्रीयतावाद प्लस स्वायत्तता
यूं सुक-योल	5	10	0	0
मून जे-इन	0	0	10	5

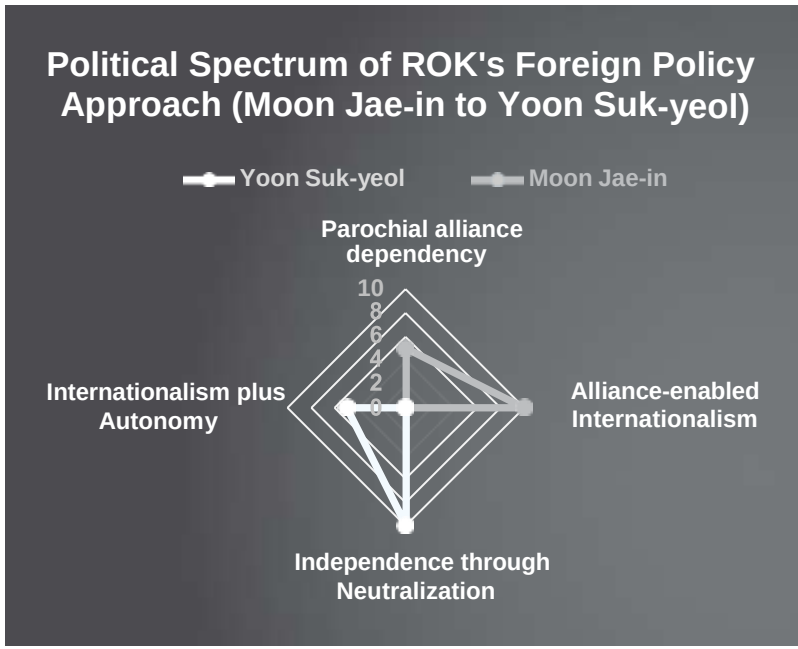

ग्राफ़ 1: कोरिया गणराज्य की विदेश नीति दृष्टिकोण का राजनीतिक स्पेक्ट्रम

जिसे मून सरकार ने एनएसपी के माध्यम से तब अपनाया जब उसने आसियान और भारत के साथ अपने संबंधों को अन्य प्रमुख शक्तियों के स्तर तक बढ़ाने की मांग की, जबकि राष्ट्रपति यून की नीति कोरिया गणराज्य-यूएस गठबंधन को छोड़ने को नहीं दर्शाती है और इसका दृष्टिकोण बहुत ही आउटवार्ड है।

अंतर्राष्ट्रीयवाद प्लस स्वायत्तता एक ऐसा दृष्टिकोण है जो कोरिया गणराज्य के अपने हितों या मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए अन्य क्षेत्रीय या वैश्विक साझेदारियों के साथ अमेरिका के साथ गठबंधन को संतुलित करता है। यह दृष्टिकोण एक बाहरी अभिविन्यास को दर्शाता है जो अंतरराष्ट्रीय मामलों की विविधता और जटिलता को पहचानता है, साथ ही स्वायत्तता में वृद्धि करता है जो कोरिया गणराज्य की स्वतंत्रता या नेतृत्व का दावा करता है। प्रगतिशील प्रशासन के कार्यकाल के दौरान यह दृष्टिकोण स्पष्ट रहा है। वैसे इसका सबसे ताज़ा उदाहरण राष्ट्रपति मून का कार्यकाल हो सकता है, जिन्होंने अमेरिका के साथ कम निर्भर संबंधों, उत्तर कोरिया के साथ अधिक रचनात्मक जुड़ाव और क्षेत्रीय मुद्दों में अधिक सक्रिय भूमिका की वकालत की। अमेरिका के साथ कम आश्रित संबंधों को आगे बढ़ाने की धारणा अमेरिकी-चीन प्रतिद्वंद्विता से बचाव के लिए आई। मून जे-इन की अध्यक्षता में, देश उत्तर कोरियाई मुद्दे को हल करने के साधन ढूंढ रहा था, और अपने हितों और मूल्यों की पूर्ति के लिए जब दक्षिण चीन सागर और चीन के आक्रामक रुख के संदर्भ में अधिक वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाने की बात आई तो सियोल रणनीतिक रूप से अस्पष्ट था। इसलिए, जब वैश्विक नेतृत्व की भूमिका के निर्णय लेने पड़ते थे तो कई बार कोरिया गणराज्य असंवेदनशील होता था। इसलिए, राष्ट्रपति मून की नीतियां इस दृष्टिकोण के कुछ हिस्सों को प्रतिबिंबित करती हैं लेकिन जब पूर्ण पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीयवाद-आधारित एजेंडे की बात आती है तो इसमें कमी थी।

गठबंधन-सक्षम अंतर्राष्ट्रीयवाद एक दृष्टिकोण है जो अन्य क्षेत्रीय या वैश्विक अभिनेताओं के साथ सहयोग या प्रतिस्पर्धा करते हुए कोरिया गणराज्य की वैश्विक भूमिका और प्रभाव का विस्तार करने के लिए एक मंच के रूप में अमेरिका के साथ गठबंधन का उपयोग करता है। यह दृष्टिकोण एक बाहरी अभिविन्यास को दर्शाता है जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भाग लेने या आकार देने के साथ-साथ एक गठबंधन सक्षमता को दर्शाता है जो अमेरिकी समर्थन या साझेदारी से लाभान्वित होता है।

शीत युद्ध के बाद के युग (1988-2007) के दौरान यह दृष्टिकोण प्रमुख था, जब कोरिया गणराज्य ने "नॉर्डपोलिटिक", "न्यू एशिया इनिशिएटिव", "ग्लोबल कोरिया" आदि के नारों के अधीन एक सक्रिय कूटनीति अपनाई थी। वर्तमान यूं सुक-योल प्रशासन (2022-वर्तमान) के लिए, यह स्पष्ट है कि उनका दृष्टिकोण गठबंधन-सक्षम अंतर्राष्ट्रीयतावाद के साथ लागू होता है जैसा कि उनकी इंडो-पैसिफ़िक रणनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के माध्यम से अनुमान लगाया जा सकता है, जो कोरिया गणराज्य के राष्ट्रीय हितों और मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए क्षेत्रीय और वैश्विक साझेदारी के लिए अमेरिकी गठबंधन को प्रोत्साहन देता है। दूसरी ओर, राष्ट्रपति मून का प्रशासन कोरिया गणराज्य की वैश्विक भूमिका और प्रभाव का विस्तार करने के लिए अमेरिका के साथ अपने गठबंधन का उपयोग करने के लिए अनिच्छुक था।

संकीर्ण गठबंधन निर्भरता एक ऐसा दृष्टिकोण है जो अन्य क्षेत्रीय या वैश्विक प्रतिबद्धताओं की उपेक्षा या विरोध करते हुए कोरिया गणराज्य की सुरक्षा और समृद्धि के एकमात्र गारंटर के रूप में अमेरिका के साथ गठबंधन को प्राथमिकता देता है। यह दृष्टिकोण एक आंतरिक अभिविन्यास को दर्शाता है जो घरेलू मुद्दों या प्रायद्वीपीय मामलों के साथ-साथ गठबंधन निर्भरता पर केंद्रित है जो सुरक्षा या मार्गदर्शन के लिए अमेरिका पर निर्भर करता है। यह दृष्टिकोण शीत युद्ध काल (1953-1987) के दौरान प्रचलित था, जब कोरिया गणराज्य को उत्तर कोरिया से अस्तित्व के ख़तरे का सामना करना पड़ा था और अन्य देशों के साथ उसके राजनयिक संबंध सीमित थे। राष्ट्रपति यून के कार्यकाल को संकीर्ण गठबंधन निर्भरता के टुकड़े कहा जा सकता है क्योंकि उनकी सरकार ने अमेरिका के साथ कोरिया गणराज्य के गठबंधन को बढ़ाया और उन्नत किया है। हालाँकि, राष्ट्रपति यून के अधीन कोरिया गणराज्य ने किसी भी अन्य क्षेत्रीय या वैश्विक जुड़ाव की उपेक्षा या विरोध नहीं किया है, जैसा कि इसकी इंडो-पैसिफ़िक रणनीति, जापान के साथ संबंधों के पुनर्मूल्यांकन और नाटो के साथ साझेदारी के विस्तार के माध्यम से देखा जा सकता है। यह इंगित करता है कि कैसे राष्ट्रपति यून के अधीन कोरिया गणराज्य बड़े पैमाने पर बाहर की ओर उन्मुख है, और इसका ध्यान कोरियाई प्रायद्वीप से लेकर व्यापक इंडो-पैसिफ़िक तक है। इसके विपरीत, राष्ट्रपति मून की नीति में अमेरिका के साथ

कोरिया गणराज्य की विदेश नीति कूटनीति एक ऐसे चौराहे से गुज़री जहां उसे प्रतिद्वंद्वी शक्तियों के युग में अमेरिका के साथ अपने गठबंधन और अपनी स्वायत्तता को संतुलित करना था, एक "वैश्विक निर्णायक राज्य" बनने की अपनी आकांक्षाओं को स्वीकार करने और साझेदारी का विस्तार करने के साथ-साथ गठबंधन को मजबूत करने की दिशा में, जैसा कि आवश्यक समझा गया था।

अपने पारंपरिक गठबंधन को प्राथमिकता देने की कोई गुंजाइश नहीं थी।

राष्ट्रपति यूं सुक-योल के अधीन, उनके पूर्ववर्ती से एक विशिष्ट विचलन है जो ज्यादातर अंतर-कोरियाई सहयोग पर केंद्रित था। यह रूढ़िवादी नेतृत्व की वापसी है और यूएस-कोरिया गणराज्य गठबंधन की बहाली की ओर वापसी है जो पूर्ववर्ती कार्यकाल के दौरान उत्तर कोरिया के साथ प्रेमालाप पर गलत जोर देने के कारण कमजोर हो गया था। राष्ट्रपति यूं सुक-योल की सरकार "वैश्विक निर्णायक राज्य" बनाने के साथ-साथ यूएस-कोरिया गणराज्य गठबंधन पर अपने जोर को फिर से संगठित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है।

अंत में, कोरिया गणराज्य को भू-राजनीतिक माहौल, सापेक्ष क्षमता, घरेलू राजनीति से निपटना होगा और चार संभावित दृष्टिकोणों में से रणनीतिक विकल्प चुनना होगा: संकीर्ण गठबंधन निर्भरता, गठबंधन-सक्षम अंतर्राष्ट्रीयतावाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद प्लस स्वायत्तता, और तटस्थता के माध्यम से स्वतंत्रता। कोरिया गणराज्य की विदेश नीति कूटनीति एक क्रॉसरोड से गुज़री है जहां इसे प्रतिद्वंद्वी शक्तियों के युग में अमेरिका के साथ अपने गठबंधन और अपनी स्वायत्तता को संतुलित करना था, एक "वैश्विक निर्णायक राज्य" बनने की अपनी आकांक्षाओं को स्वीकार करना और साझेदारी का विस्तार करने के साथ-साथ गठबंधन को मजबूत करना, जैसा कि आवश्यक समझा गया था।

3. इंडो-पैसिफ़िक भूरणनीतिक फ्रेमवर्क की ओर कोरिया गणराज्य का संक्रमण: प्रगति या निरंतरता?

इस पेपर में अध्ययन के माध्यम से, यह पता लगाया जा सकता है कि मून जे-इन और यूं सुक-येओल प्रशासन अपने विदेशी नीति दृष्टिकोण के मामले में अलग-अलग स्पेक्ट्रम पर काम कर रहे हैं। यह प्रश्न बना हुआ है कि क्या सरकार के परिवर्तन के परिणामस्वरूप 2017 के बाद से विदेश नीति दृष्टिकोण में प्रगति या निरंतरता आई है। जैसा कि पहले बताया गया है, एनएसपी और एनएसपी प्लस रणनीतियां आर्थिक पहलुओं के साथ-साथ गूंजती हैं, जिसका लक्ष्य सियोल की साझेदारी को उसके पारंपरिक सहयोग से विविधता प्रदान करना है; यह इस बात की याद दिलाता है कि आर्थिक विकास विदेशी संबंधों को कैसे प्रभावित करता है।[85] सियोल अमेरिका, चीन, जापान और रूस पर अत्यधिक निर्भर हो गया था। लेकिन वैश्विक प्रवाह के कारण कोरिया गणराज्य को अपने आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए अपनी विदेश नीति पर फिर से विचार करने की आवश्यकता पड़ी, साथ ही अमेरिका के साथ अपने गठबंधन के माध्यम से पारंपरिक रूप से समर्थित सुरक्षा विचारों पर भी जोखिम उठाना पड़ा। इसलिए, मून जे-इन युग के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली में अधिक प्रमुखता से शामिल होने के लिए कोरिया गणराज्य ने अमेरिका और चीन के बीच किसी भी पक्ष को न चुनने के लिए एक बचाव दृष्टिकोण अपनाया, और इसलिए एनएसपी और बाद में एनएसपी प्लस के माध्यम से अपने हितों का विस्तार करने और विदेश नीति लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपने साधनों को बढ़ाने का फैसला किया।

2017 और 2022 के बीच, ROK द्वारा शुरू की गई विदेश नीति ने कोरिया गणराज्य अमेरिकी गठबंधन पर उनकी निर्भरता को

85 U. Heo and T. Roehrig, 2014, *South Korea's Rise: Economic Development, Power, and Foreign Relations*, Cambridge: Cambridge University Press, doi:10.1017/CBO9780511998355

कम करने के लिए रणनीतिक निर्णय लेने में स्वायत्तता के आधार को व्यक्त किया, जो परंपरागत रूप से उदारवादी पार्टियों की विदेश नीति का एजेंडा रहा है, जबकि इसके प्रमुख व्यापार भागीदार चीन और इसके संधिगत रूप से अमेरिका के बीच संबंधों को आगे बढ़ाया गया है। आसियान और भारत के माध्यम से घनिष्ठ संबंध को बढ़ावा देने की रूपरेखा पर, एनएसपी और एनएसपी प्लस की नीतियों को कोरिया गणराज्य के विदेशी मामलों में पारंपरिक प्रमुख खिलाड़ियों, अमेरिका, चीन, रूस और जापान को संतुलित करने के लिए अपनाया गया था। हालाँकि, कोरिया गणराज्य भू-राजनीति की बदलती धाराओं का सामना करने वाली एक मध्य शक्ति के रूप में अपनी भूमिका में रणनीतिक रूप से अस्पष्ट था।

कोरिया गणराज्य के नए राष्ट्रपतिके रूप में चुने जाने के बाद, यूं सुक-योल ने कोरिया गणराज्य को "वैश्विक निर्णायक राज्य" बनाने के एजेंडे को आगे बढ़ाया। उनके प्रशासन ने 28 दिसंबर 2022 को कोरिया गणराज्य की पहली आधिकारिक इंडो-पैसिफ़िक रणनीति पेश की। दस्तावेज़, "एक स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और समृद्ध इंडो-पैसिफ़िक के लिए रणनीति", ने "वैश्विक निर्णायक राज्य" के उद्देश्यों को आगे बढ़ाया"।[86] एनएसपी और एनएसपी प्लस पहल पर आधारित, इंडो-पैसिफ़िक रणनीति का उद्देश्य इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र में दक्षिण कोरिया की भागीदारी को बढ़ाना है, क्योंकि यह देश के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक और सुरक्षा महत्व रखता है।[87] इंडो-पैसिफ़िक रणनीति दस्तावेज़ ने न केवल आसियान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के साथ संबंध बनाने के महत्व को रेखांकित किया, लेकिन प्रशांत द्वीप देशों (पीआईसी) और अफ्रीका के साथ भी। जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य देखभाल, महासागरों और मत्स्य पालन, और प्रशांत द्वीप समूह द्वारा अनुभव की जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा चुनौतियों जैसी चिंताओं पर जोर देते हुए, रणनीति में ब्लू पैसिफ़िक महाद्वीप के लिए 2050 की

86 *Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea*, 2022, "Strategy for a Free, Peaceful, and Prosperous Indo-Pacific Region", 28 December 2022, https://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5676/view.do?seq=322133&page=1

87 Tunchinmang Langel, 2023, "Deconstructing Republic of Korea's (ROK) 'Strategy for a Free, Peaceful and Prosperous Indo-Pacific' ", *ICWA*, 31 January 2023, https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=8975&lid=5849

रणनीति के साथ-साथ पार्टनर्स इन द ब्लूपैसिफ़िक (पीबीपी) पहल का समर्थन करने को प्राथमिकता दी गई है। दक्षिण कोरिया ने अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने और विस्तार करने में अपनी गहरी रुचि भी व्यक्त की। दक्षिण कोरिया कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला और अन्य खनिजों जैसे आवश्यक संसाधनों के सुरक्षित समुद्री परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में अफ्रीकी तट के साथ, एक स्थिर उपस्थिति बनाए रखने की आवश्यकता को पहचानता है।

जैसा कि पहले निर्दिष्ट किया गया है, इंडो-पैसिफ़िक रणनीति इस बात पर प्रकाश डालती है कि दक्षिण कोरिया ने बढ़ती वैश्विक और इंडो-पैसिफ़िक सुरक्षा चुनौतियों को पहचानने में अपनी पिछली हिचकिचाहट को दूर कर लिया है। यूं सुक-येओल सरकार के अधीन, दक्षिण कोरिया "वैश्विक निर्णायक राज्य" बनने के अपने लक्ष्य के अनुरूप, आर्थिक और सुरक्षा दोनों पहलुओं में सहयोग के अवसरों को सक्रिय रूप से तलाशने में एक प्रमुख भागीदार के रूप में अपनी तैयारियों पर जोर देता है। यह बदलाव जो इंडो-पैसिफ़िक जल की सुरक्षा के आर्थिक और सुरक्षा विचारों को जोड़ता है, पिछले प्रशासन की तुलना में कोरिया गणराज्य की विदेश नीति के दृष्टिकोण में एक उल्लेखनीय परिवर्तन को दर्शाता है।[88]

इस पेपर में किए गए विश्लेषण से पता चलता है कि राष्ट्रपति मून और राष्ट्रपति यून की सरकारें विपरीत विचारधारा पर काम कर रही हैं। राष्ट्रपति मून के दृष्टिकोण "निष्प्रभावीकरण के माध्यम से स्वतंत्रता" के अनुरूप थे, और इसके अमेरिका के संतुलन ने सीमित दायरे के बावजूद "अंतर्राष्ट्रीयता प्लस स्वायत्तता" पहलू को चित्रित किया। राष्ट्रपति मून के अधीन कोरिया गणराज्य रणनीतिक रूप से अस्पष्ट था और सक्रिय वैश्विक कूटनीति कदम उठाने के मामले में उत्तर कोरियाई मुद्दे पर काफी हद तक प्रतिबंधित था।

88 Tunchinmang Langel, 2023, "Deconstructing Republic of Korea's (ROK) 'Strategy for a Free, Peaceful and Prosperous Indo-Pacific' ", *ICWA*, 31 January 2023, https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=8975&lid=5849

वहीं दूसरी ओर, राष्ट्रपति यून का नीतिगत दृष्टिकोण बहिर्मुखी, भविष्योन्मुखी, कट्टरपंथी और साझेदारी निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने वाला रहा है और और वैश्विक एजेंडा स्थापित करने और कोरियाई प्रायद्वीप से व्यापक इंडो-पैसिफ़िक तक देश के परिप्रेक्ष्य का विस्तार करने में कोरिया गणराज्य को शामिल करने के लिए समान विचारधारा वाले दलों के साथ साझेदारी और गठबंधन बनाने पर ध्यान केंद्रित करना।

कुल मिलाकर, यहां प्रस्तुत विश्लेषण एक विकास को रेखांकित करता है क्योंकि कोरिया गणराज्य एक इंडो-पैसिफ़िक भू-रणनीतिक ढांचे की ओर संक्रमण कर रहा है। इसने अपनी रणनीतिक अस्पष्टता को त्याग दिया है और ऐसी नीतियां जारी करने का निर्णय लिया है जो दीर्घकालिक हैं और यहां तक कि पक्षपातपूर्ण घरेलू राजनीति को भी खत्म कर सकती हैं।

4. कोरिया गणराज्य का इंडो-पैसिफ़िक को गले लगाना: भारत के लिए इसका क्या अर्थ है?

2017 में, सियोल की रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ाने के लिए, राष्ट्रपति मून जे-इन ने आर्थिक विविधता के लिए भारत और आसियान की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए एनएसपी की शुरुआत की, चूँकि अमेरिका और चीन के बीच प्रतिद्वंद्विता की तीव्रता ने सियोल की नीतिगत विकल्पों पर भारी बाधाएँ डाल दी थीं। नई दिल्ली ने मौलिक मूल्यों और रणनीतिक हितों को भी साझा किया, जिसे सियोल ने मुखर चीन के साथ संतुलन बनाने के लिए महत्वपूर्ण पाया। भारत और कोरिया गणराज्य के द्विपक्षीय संबंध, जिसे मई 2015 में "विशेष रणनीतिक साझेदारी" तक बढ़ा दिया गया था, 2017 में एनएसपी की शुरूआत के साथ उसे एक प्रोत्साहन मिला था, क्योंकि भारत को कोरिया गणराज्य की नई नीति के लिए एक केंद्रीय स्तंभ माना गया था।[89] दक्षिण कोरिया की विदेश नीति के कई विशेषज्ञों द्वारा यह पहले ही स्थापित किया

89 *Embassy of India*, 2022, "India and Republic of Korea: A Vision for People, Prosperity, Peace and our Future", 10 November 2022, https://www.indembassyseoul.gov.in/india-and-republic-korea-vision-people-prosperity-peace-and-our-future

जा चुका है कि एनएसपी अमेरिका-चीन रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच एक बचाव मंच था।[90] अंततः, एनएसपी को "विकासात्मक सहायता के साथ आर्थिक और कार्यात्मक सहयोग कार्यक्रम" तक ही सीमित कर दिया गया और यह व्यापक क्षेत्रीय राजनीतिक और सुरक्षा मामलों में प्रभावी ढंग से शामिल नहीं हो सका"।[91] इसके अलावा, भारत ने उस समय इंडो-पैसिफ़िक अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, खासकर दिसंबर 2015 में हस्ताक्षरित भारत-जापान विज़न2025 के साथ। दूसरी ओर, कोरिया गणराज्य को अभी भी आपत्ति थी और वह अपने दृष्टिकोण में अभी भी अस्पष्ट था, तब भी जब उसके गठबंधन सहयोगी अमेरिका ने 2017 में अपनी इंडो-पैसिफ़िक रणनीति पहले ही जारी कर दी थी। राष्ट्रपति मून के अधीन कोरिया गणराज्य अपनी स्थिति की किसी भी अभिव्यक्ति पर अस्पष्टता बनाए हुए था और इंडो-पैसिफ़िक अवधारणा का समर्थन करने के लिए अनिच्छुक प्रतीत होता था।

हालाँकि, राष्ट्रपति यूं सुक-योल के आगमन के साथ, रणनीतिक दृष्टिकोण के मामले ने अधिक सक्रिय दृष्टिकोण ले लिया है। यह पहले से ही स्पष्ट है कि नए राष्ट्रपति ने 2022 में आधिकारिक तौर पर अपनी पहली इंडोपैसिफ़िक रणनीति जारी करके कोरिया गणराज्य को "वैश्विक निर्णायक राज्य" में बढ़ाने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। इसके परिणामस्वरूप परमाणु निवारण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अमेरिका के साथ अपने गठबंधन के उन्नयन पर जोर दिया गया, और राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्र

90 Choe Wongi, 2023, "South Korea's New Southern Policy: The Limits of Indo-Pacific Geopolitics", in Peng Er, L. (Ed.), *South Korea's New Southern Policy: A Middle Power's International Relations with Southeast Asia and India* (1st ed.), Chapter 2, pp. 19-41, Routledge, https://doi.org/10.4324/9781003353133

91 Choe Wongi, 2023, "South Korea's New Southern Policy: The Limits of Indo-Pacific Geopolitics", in Peng Er, L. (Ed.), *South Korea's New Southern Policy: A Middle Power's International Relations with Southeast Asia and India* (1st ed.), Chapter 2, pp. 19-41, Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003353133

यह उम्मीद की जाती है कि कोरिया गणराज्य ने अपने इंडो-पेसिफ़िकभू-रणनीतिक ढांचे के संदर्भ में आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, भारत और कोरिया गणराज्य के बीच द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा।

की सुरक्षा, परमाणु निरस्त्रीकरण के माध्यम से कोरियाई प्रायद्वीप में शांति और कोरिया गणराज्य के लिए वैश्विक भूमिका की वकालत करने वाले एनएसएस को प्रकाशित किया गया। कोरिया गणराज्य द्वारा इंडो-पैसिफ़िक को अपनाने से सियोल की स्थिति और अवधारणा के समर्थन के संबंध में अभिव्यक्ति में किसी भी तरह की हिचकिचाहट दूर हो गई है। यह भारत-कोरिया गणराज्य की विशेष रणनीतिक साझेदारी के लिए भी एक स्वागत योग्य कदम है।

यह उम्मीद की जाती है कि कोरिया गणराज्य ने अपने इंडो-पैसिफ़िक भू-रणनीतिक ढांचे के संदर्भ में आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, भारत और कोरिया गणराज्य के बीच द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। जैसे-जैसे दुनिया भू-राजनीति में अभूतपूर्व बदलाव से गुजर रही है, नई दिल्ली और सियोल अपने इंडो-पैसिफ़िक ढांचे के साथ इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए मिलकर काम करने का एक उपयुक्त अवसर मानेंगे। कई कारकों, जिनमें से एक यूक्रेन संघर्ष है, ने खाद्य और ऊर्जा संकट जैसे सभी मोर्चों पर असाधारण चुनौतियाँ पेश की हैं। अमेरिका और चीन के बीच महान शक्ति प्रतिद्वंद्विता के कारण भी आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। चीन की आक्रामक नीतियों ने खुले समुद्र में नौवहन की स्वतंत्रता को ख़तरे में डालना जारी रखा है, जिससे दक्षिण चीन सागर और ताइवान जलडमरूमध्य में क्षेत्रीय संप्रभुता और अखंडता विवाद बढ़ रहे हैं। उत्तर कोरिया द्वारा दक्षिण कोरिया के क्षेत्रीय समुद्र में बैलिस्टिक मिसाइलों का उकसाने वाला परीक्षण लॉन्च किया जाना और जापान ने सार्वभौमिक और गैर-भेदभावपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्यों और सामूहिक विनाश के हथियारों के अप्रसार और उनकी वितरण प्रणालियों के उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्धता का आह्वान करने की

अधिक आवश्यकता पैदा की है।[92] गंभीर और मांग वाली चुनौतियों के लिए भारत और कोरिया गणराज्य को अपने इंडोपैसिफ़िक दृष्टिकोण के माध्यम से वर्तमान भू-राजनीतिक चिंताओं पर तालमेल बिठाने की और रक्षा सहयोग सहित संपूर्ण स्पेक्ट्रम में अपनी साझेदारी को मजबूत करने की आवश्यकता है।

कोरिया गणराज्य ने अंततः इंडो-पैसिफ़िक को गले लगा लिया है और वैश्विक शासन के मुद्दों पर विशेष रूप से आर्थिक और सुरक्षा एजेंडा के ओवरलैपिंग को प्राथमिकता देते हुए अपनी स्थिति का खुले तौर पर समर्थन किया है, द्विपक्षीय संबंधों में ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जो दोनों देशों के बीच रणनीतिक और सुरक्षा हितों के अभिसरण के रूप में उभर रहे हैं। रक्षा सहयोग पहले से ही भारत-कोरिया विशेष रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। भारत और दक्षिण कोरिया ने 2019 में एक लॉजिस्टिक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए, जो दक्षिण कोरिया के बंदरगाहों में इंडो-पैसिफ़िक में संचालन के दौरान भारतीय नौसेना के लिए रसद सहायता का आश्वासन देता है। भारतीय युद्धपोत आईएनएस सुमेधा और कोरिया गणराज्य के नौसेना जहाज हंसांडो और डे चेओंग ने 1 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया।[93] ऐसे अभ्यासों को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है क्योंकि ये दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग और अंतरसंचालनीयता को मजबूत करने के लिए पारस्परिक रूप से लाभप्रद साबित होते हैं।[94] चीनी नौसेना की बढ़ती उपस्थिति के जवाब में भारत भी अपनी नौसैनिक क्षमताओं को उन्नत करने का प्रयास कर रहा है। इस पहलू में, नौसैनिक जहाज निर्माण

92 *ANI*, "India, South Korea discuss disarmament, non-proliferation", 31 March 2022, https://aninews.in/news/world/asia/india-south-korea-discuss-disarmament-non-proliferation20220331230432/

93 *The Hindu*, 2022, "Two Korean naval ships arrive in Chennai on a four-day visit; to hold joint exercise with Indian Navy", 28 September 2022, https://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/two-korean-naval-ships-arrive-in-chennai-on-a-four-day-visit-to-hold-joint-exercise-with-indian-navy/article65945974.ece

94 Jude Sannith, 2022, "South Korean warships Hasando and Daechong dock in Chennai for 'Passex' operations with Indian Navy", 28 September 2022, https://www.cnbctv18.com/india/south-korean-warships-hasando-and-daechong-dock-in-chennai-for-passex-operations-with-indian-navy-14821781.htm

एसएलओसी की सुरक्षा और सुरक्षा, विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में, दक्षिण कोरिया के लिए महत्वपूर्ण है, और भारत अपनी भू-रणनीतिक स्थिति के साथ दक्षिण कोरिया के लिए एक आदर्श रक्षा और सुरक्षा भागीदार बन गया है।

और पनडुब्बी निर्माण जैसे क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत और कोरिया सहयोग कर सकते हैं, चूंकि कोरिया गणराज्य एक प्रौद्योगिकी अग्रणी है और सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी नौसैनिक जहाज निर्माण उद्योगों में से एक है। हालाँकि, रक्षा सहयोग पर स्थानीय अपेक्षाओं और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आवश्यकताओं में अभी भी अंतर हैं।

दक्षिण कोरिया पहले ही हिंद महासागर में संचार की समुद्री लाइनों (एसएलओसी) को सुरक्षित करने में अपनी रुचि प्रदर्शित कर चुका है, जो ऊर्जा आयात की प्रमुख मार्ग हैं। कोरिया अपनी तेल खपत का लगभग 60% केवल पश्चिम एशिया से आयात करता है। दक्षिण कोरिया तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी), कोयला और टोटल पेट्रोलियम लिक्विड्स के दुनिया के शीर्ष पांच आयातकों में से एक है। दक्षिण कोरिया विशेष रूप से एलएनजी और कच्चे तेल के टैंकर शिपमेंट पर निर्भर है। इसलिए, एसएलओसी की सुरक्षा और सुरक्षा, विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में, दक्षिण कोरिया के लिए महत्वपूर्ण है, और भारत अपनी भू-रणनीतिक स्थिति के साथ दक्षिण कोरिया के लिए एक आदर्श रक्षा और सुरक्षा भागीदार बन गया है। नतीजतन, हिंद महासागर क्षेत्र और उससे परे एक पसंदीदा सुरक्षा भागीदार के रूप में भारत का अनुभव और भूमिका एसएलओसी को सुरक्षित करने के लिए कोरिया गणराज्य की आवश्यकता के लिए एक वरदान होगी।

भारत और दक्षिण कोरिया वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लचीलेपन और मजबूती को बढ़ाने पर सहयोग करने के लिए भी आम सहमति पर पहुंचे हैं। उन्होंने उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग के संभावित अवसरों की भी तलाश की। जनवरी 2023 में सियोल, दक्षिण कोरिया में आयोजित 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता (एफपीएसडी)

फ़्रॉम न्यू सदर्न पॉलिसी टू द इंडो-पेसिफ़िक स्ट्रेटेजी

के दौरान, भारत के विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) सौरभ कुमार ने कहा, कोरियाई प्रतिनिधिमंडल को भारत में कोरियाई कंपनियों के लिए विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और विभिन्न अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध निवेश के अवसरों के बारे में जानकारी दी।[95]

त्रिपक्षीय सहयोग पर भी सुझाव आये हैं। वियतनाम और कोरिया गणराज्य ने हाल ही में व्यापक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है, और भारत की कोरिया और वियतनाम दोनों के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी है, यह इंडो-पेसिफ़िकक्षेत्र में शांति और समृद्धि लाने के लिए रक्षा, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग के लिए एक नया सहयोगात्मक दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है।[96] अन्य त्रिपक्षीय सहयोग भारत-जापान-कोरिया गणराज्य और भारत-कोरिया गणराज्य-इंडोनेशिया हो सकते हैं।

कोरिया गणराज्य ने एक आसियान-विशिष्ट योजना का भी अनावरण किया, जिसे कोरिया-आसियान सॉलिडेरिटी इनिशिएटिव (KASI) कहा जाता है, जो कोरिया गणराज्य की इंडो-पेसिफ़िकरणनीति का एक मुख्य घटक बनेगा। इस संबंध में, भारत कोरिया की क्षेत्रीय रणनीतिक और आर्थिक पहुंच को बढ़ाने के लिए एक आदर्श भागीदार हो सकता है। इसे भारत की अपनी इंडो-पैसिफ़िक महासागर पहल (आईपीओआई) के माध्यम से हासिल किया जा सकता है, जिसकी घोषणा 4 नवंबर 2019 को बैंकॉक में 14वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान सहयोग के सात स्तंभों के साथ की गई थी:

- समुद्री पारिस्थितिकी
- समुद्री सुरक्षा

95 *Ministry of External Affairs, Government of India*, 2023, "5th India-RoK Foreign Policy and Security Dialogue (FPSD)", 17 January 2023, https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/36128/5th_IndiaRoK_Foreign_Policy_and_Security_Dialogue_FPSD

96 From ICWA-RIS and KNDA-KIEP First 2+2 Dialogue, 27 October 2021

- समुद्री संसाधन
- क्षमता निर्माण और संसाधन साझा करना
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन
- विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शैक्षणिक सहयोग
- व्यापार, कनेक्टिविटी और समुद्री परिवहन

विशेष रणनीतिक साझेदारी के अनुसार, कोरिया गणराज्य समुद्री सुरक्षा स्तंभ और विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शैक्षणिक सहयोग स्तंभ में शामिल होने या नेतृत्व करने के लिए अच्छा काम करेगा।

इस अध्ययन के अनुसार, कोरिया गणराज्य द्वारा इंडो-पैसिफ़िक को अपनाने और भारत इस अवधारणा का लगातार समर्थक होने के कारण, कुछ सिफारिशें हैं जिन पर अगले 50 वर्षों तक ध्यान केंद्रित किया जा सकता है:

- रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ध्यान दें। एक रणनीतिक स्तंभ के निर्माण की आवश्यकता है जो रक्षा उद्योग और भविष्य की प्रौद्योगिकियों में सहयोग सुनिश्चित करेगा।
- कोरिया गणराज्य की रक्षा और जहाज निर्माण कंपनियों को भारत के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
    - ❖ रक्षा सहयोग की मजबूती को एलएंडटी द्वारा असेंबल किए गए दक्षिण कोरिया के के-9 वज्र हॉवित्जर के उदाहरण से देखा जा सकता है - 100 पहले ही भारतीय सेना में शामिल किए जा चुके हैं और 100 अतिरिक्त ऑर्डर वर्तमान में प्रक्रिया में हैं।[97]
    - ❖ इसी तरह, अत्याधुनिक पनडुब्बी प्रौद्योगिकी और उन्नत प्रणालियों में कोरिया गणराज्य के विशाल

97 Kapil Kajal, 2023, "Indian Army orders 100 additional K9 Howitzers", *Janes*, 20 February 2023, https://www.janes.com/defence-news/news-detail/indian-army-orders-100-additional-k9-howitzers

अनुभव के साथ, भारत की अगली पीढ़ी की पनडुब्बी परियोजना (प्रोजेक्ट 75) सियोल के नए इंडोपैसिफ़िक आउटरीच के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश प्रदान करती है।[98]

- दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास को नियमित और संस्थागत बनाना।
- आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और उद्योगों के स्थानांतरित होने से अवसर पैदा हुए हैं, और कोरिया गणराज्य भारत को सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र बनने में भी मदद कर सकता है।
- इंडो-पैसिफ़िक में महान शक्ति प्रतिद्वंद्विता के कम करने वाले परिणामों से निपटने के लिए वियतनाम-भारत-कोरिया गणराज्य, कोरिया गणराज्य-भारत-जापान और भारत-कोरिया गणराज्य-इंडोनेशिया के बीच एक त्रिपक्षीय तंत्र के लिए एक मंच प्रदान करें।

यहां तक कि साझेदारी के व्यापार और निवेश पहलू को भी आगे बढ़ाया जा सकता है, जो 2017 से बढ़ रहा है।

तालिका 2

क्र.सं.	\वर्ष	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
1.	निर्यात	4,460.98	4,705.07	4,845.15	4,684.62	8,085.03	6,654.10
2.	%वृद्धि		5.47	2.98	-3.31	72.59	-17.70
6.	Import आयात	16,361.77	16,758.97	15,659.70	12,772.97	17,477.20	21,227.32
7.	%वृद्धि		2.43	-6.56	-18.43	36.83	21.46
11.	कुल व्यापार	20,822.75	21,464.04	20,504.85	17,457.59	25,562.24	27,881.42
12.	%वृद्धि		3.08	-4.47	-14.86	46.42	9.07
16.	व्यापार-संतुलन	-11,900.80	-12,053.90	-10,814.55	-8,088.35	-9,392.17	-14,573.21

स्रोत: वाणिज्य विभाग, निर्यात-आयात डेटा बैंक

98 Manish Kumar Jha, 2023, "After Hanwha's K-9 Vajra, submarines are the potential area to collaborate with India, says Kim Dae-Young, EVP", *Financial Express*, 28 June 2023, https://www.financialexpress.com/business/defence-after-hanwhas-k-9-vajra-submarines-are-the-potential-area-to-collaborate-with-india-says-kim-dae-young-evp-3144944/

वाणिज्य विभाग, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट डेटा बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत और दक्षिण कोरिया का कुल द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में 27.88 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। यह पिछले वर्ष से 9.07 प्रतिशत की वृद्धि थी, शायद यह संकेत दे रहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधाएं वापस कोविड-पूर्व चरण में लौट रही हैं।

यदि हम विशिष्ट बातों को देखें, तो आंकड़े बताते हैं कि भारत ने 2022-23 में कोरिया गणराज्य को 6.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया, जबकि 2022-23 में ROK से भारत का आयात 21.23 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। 2022-23 में भारत से कोरिया गणराज्य को निर्यात की मात्रा में 17.70 प्रतिशत की गिरावट आई है। 2022-23 में आयात की मात्रा 21.46 प्रतिशत बढ़ी, लेकिन 2021-22 की 36.83 प्रतिशत की वृद्धि से कम है। वर्ष 2021-22 के दौरान, लौह अयस्क (215.5 प्रतिशत वृद्धि) और एल्यूमीनियम (143.6 प्रतिशत वृद्धि) सहित भारत से कोरिया गणराज्य को निर्यात की गई सभी प्रमुख वस्तुओं में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। 2021-22 में कोरिया से सबसे अधिक आयातित वस्तुओं में इलेक्ट्रिकल मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (30.47 प्रतिशत वृद्धि) और आयरन एंड स्टील (53.39 प्रतिशत वृद्धि) शामिल हैं। हालाँकि, भारतीय वस्तुओं के लिए बाज़ार पहुंच संबंधी कुछ मुद्दों के कारण व्यापार संतुलन अभी भी घाटे में बना हुआ है। चूंकि व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर वर्तमान में बातचीत चल रही है, भारत एक ऐसे समझौते पर पहुंचने के लिए उत्सुक है जो दोनों पक्षों के आपसी हितों को संबोधित करेगा और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत और गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। परिणामस्वरूप, 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक दोगुना करने के लिए परिचालन को बढ़ाने के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

---

99 *The Economic Times*, 2022, "Bilateral trade between India and Korea grew 40% to $23.7 billion in 2021", 2 June 2022, https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/bilateral-trade-between-india-and-korea-grew-40-to-23-7-billion-in-2021/articleshow/91968386.cms

चूंकि व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर बातचीत फिलहाल चल रही है, भारत एक ऐसे समझौते पर पहुंचने की उम्मीद कर रहा है जो दोनों पक्षों के आपसी हितों को संबोधित करेगा और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत और गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

नई दिल्ली के रणनीतिक महत्व पर सियोल के अद्यतन परिप्रेक्ष्य के संकेत के रूप में, दक्षिण कोरिया की नई इंडो-पैसिफ़िक रणनीति, 28 दिसंबर 2022 को जारी की गई, जिसने भारत और दक्षिण कोरिया के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के संदर्भ में, दक्षिण कोरिया ने भारत को समान मूल्यों को साझा करने वाला एक प्रमुख क्षेत्रीय भागीदार के रूप में अपने विचारों पर जोर दिया है।[100] सियोल भारत की बड़ी कामकाजी उम्र की आबादी और आईटी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में अत्याधुनिक विशेषज्ञता द्वारा संचालित महत्वपूर्ण विकास क्षमता को पहचानता है। दक्षिण कोरिया ने विदेशी मामलों और रक्षा मामलों में उच्च स्तरीय आदान-प्रदान के माध्यम से भारत के साथ रणनीतिक संचार और सहयोग बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कोरिया गणराज्य-भारत व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) को उन्नत करने का प्रस्ताव विशेष महत्व का विषय है। इसके अलावा, दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग के मूल्य की पुष्टि उच्च-रैंकिंग अधिकारियों द्वारा चल रहे सुरक्षा और रणनीतिक संवादों के साथ-साथ ट्रैक 1.5 और ट्रैक 2 प्लेटफार्मों के माध्यम से की गई है। ये सभाएं दोनों देशों को द्विपक्षीय मामलों का व्यापक मूल्यांकन करने, पर्याप्त सहयोग बढ़ाने के रास्ते तलाशने और प्रमुख क्षेत्रीय और

100 Tunchinmang Langel, 2023, "Deconstructing Republic of Korea's (ROK) 'Strategy for a Free, Peaceful and Prosperous Indo-Pacific' ", *ICWA*, 31 January 2023, https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=8975&lid=5849

वैश्विक चिंताओं के संबंध में चर्चा में शामिल होने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं।[101]

राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से भारत और दक्षिण कोरिया के बीच संबंध मजबूत बने हुए हैं, दक्षिण कोरिया की सांस्कृतिक और सॉफ्ट पावर कूटनीति ने विश्व स्तर पर और विशेष रूप से भारत में उल्लेखनीय प्रभाव डाला है, जहां युवा कोरियाई भाषा, भोजन, संस्कृति को अपनाने और दक्षिण कोरिया में उच्च शिक्षा के अवसरों को हासिल करने में गहरी रुचि दिखाते हैं।

2023 से पहले, ROK और भारत के बीच राज्य प्रमुख स्तर की आखिरी यात्रा 2019 में हुई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी ने 21-22 फरवरी 2019 को दक्षिण कोरिया का दौरा किया। इस यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को बातचीत में गति प्रदान की और साझेदारी में गहराई से आगे बढ़ने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। वर्ष 2023 में भारत के G20 की अध्यक्षता के साथ, जिसने भारत और दक्षिण कोरिया के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के अलावा, वैश्विक दक्षिण के नेता के रूप में अपना स्थान ऊंचा किया, नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन के मौके पर राष्ट्रपति यूं सुक-योल और प्रधान मंत्री मोदी की द्विपक्षीय बैठक ने कार्यकारी नेतृत्व के माध्यम से आगे मार्गदर्शन प्रदान किया और साझेदारी में गति बनाए रखी। द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में इन पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ (1) दक्षिण कोरिया और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के जश्न में रणनीतिक संचार और सहयोग को मजबूत करना, (2) रक्षा उद्योग, आपूर्ति श्रृंखला, बुनियादी ढांचे और ईवी बैटरी प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाना, और (3) क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मूल्यों पर

101 Tunchinmang Langel, 2023, "Japan-India-South Korea Trilateral for the Indo-Pacific", *ICWA*, 19 April 2023, https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=9313&lid=6031

नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन के मौके पर राष्ट्रपति यूं सुक-योल और प्रधान मंत्री मोदी की द्विपक्षीय बैठक ने कार्यकारी अधिकारियों के माध्यम से आगे मार्गदर्शन प्रदान किया।
नेतृत्व और साझेदारी में गति बनाए रखता है।

आधारित एकजुटता को मजबूत करना।[102] इस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन ने वैश्विक शासन में उनकी नेतृत्वकारी भूमिकाओं को मजबूत करने में बहुत आवश्यक प्रोत्साहन में योगदान दिया। भारत और कोरिया सुधारित बहुपक्षवाद के संदर्भ में एक साथ सक्रिय रुख अपनाने की और इंडोपैसिफ़िक में नियम-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देते हुए समान दृष्टिकोण और सिद्धांतों को साझा करने वाले देशों के साथ व्यापक वैश्विक मुद्दों पर व्यापक सहयोग के अपने दायरे का विस्तार करने की प्रक्रिया में हैं।

निष्कर्ष:
हिंद-प्रशांत के प्रति कोरिया गणराज्य की विदेश नीति का सारांश

कोरिया गणराज्य की विदेश नीति के दृष्टिकोण में हाल के वर्षों में एनएसपी से इंडो-पैसिफ़िक रणनीति तक एक आदर्श बदलाव आया है। दिसंबर 2022 में, कोरिया गणराज्य ने अपनी इंडो-पैसिफ़िक रणनीति का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र के साथ दक्षिण कोरिया की भागीदारी का विस्तार करना है। रणनीति नियम-आधारित व्यवस्था, आर्थिक सहयोग और लोगों से लोगों के बीच आदान-प्रदान के महत्व पर जोर देती है। इससे पता चला है कि कोरिया गणराज्य अब रणनीतिक रूप से अस्पष्ट नहीं है और वैश्विक शासन के लिए एजेंडा तय करने वाले एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में अधिक भूमिका निभाने को तैयार है।

102 *Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea*, 2023, "President Yoon Seok-yeol holds summit meeting with Indian Prime Minister on the occasion of G20 summit", 11 September 2023, https://www.mofa.go.kr/www/brd/m_26079/view.do?seq=379&page=1

एनएसपी और इंडो-पैसिफ़िक रणनीति की तुलना से पता चलता है कि दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ है। एनएसपी का लक्ष्य भारत और आसियान के साथ कोरिया गणराज्य के संबंधों को चीन, जापान, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उसके संबंधों के समान स्तर पर उठाना है। इस नीति में भारत और आसियान सदस्यों के साथ सियोल के आर्थिक, राजनीतिक, रणनीतिक और सामाजिक-सांस्कृतिक सहयोग को गहरा करने और पूर्वी एशिया सहित दुनिया में पारस्परिक समृद्धि और शांति का एहसास करने का प्रयास किया गया। एनएसपी ने एक कोरिया-आसियान भावी समुदाय की कल्पना की जो 3पी पर जोर देता है: लोग, समृद्धि और शांति, जबकि इंडो-पैसिफ़िक रणनीति सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर अधिक जोर देती है, जो क्षेत्र में बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाती है। इंडो-पैसिफ़िक रणनीति पूरे इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र के साथ दक्षिण कोरिया की भागीदारी का विस्तार करना चाहती है। इस रणनीति का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, आसियान, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और प्रशांत द्वीपों के साथ दक्षिण कोरिया की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाना है ताकि क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और समृद्धि में योगदान दिया जा सके।

कुल मिलाकर, कोरिया गणराज्य की विदेश नीति के निहितार्थ के संदर्भ में, एनएसपी से इंडो-पैसिफ़िक रणनीति में बदलाव क्षेत्र में सियोल की बढ़ती रुचि और क्षेत्रीय व्यवस्था को आकार देने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की उसकी इच्छा को दर्शाता है। हालाँकि, कोरिया गणराज्य को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच प्रतिद्वंद्विता सहित क्षेत्र की जटिल भू-राजनीतिक गतिशीलता से निपटने की आवश्यकता होगी।

इस अध्ययन को आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण था क्योंकि कोरिया गणराज्य की विदेश नीति के दृष्टिकोण पर उपलब्ध विशाल साहित्य मुख्य रूप से कोरिया गणराज्य की आर्थिक कूटनीति के लेंस के माध्यम से केंद्रित है। इसलिए, कोरिया गणराज्य की विदेश नीति की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए भू-राजनीति की बदलती धाराओं के बीच सियोल की विदेश नीति दृष्टिकोण के विमर्श पर अधिक विस्तृत ध्यान देने की आवश्यकता है।

एनएसपी से इंडो-पैसिफ़िक रणनीति में बदलाव इस क्षेत्र में सियोल की बढ़ती रुचि और क्षेत्रीय व्यवस्था को आकार देने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की उसकी इच्छा को दर्शाता है।

हालाँकि, कोरिया गणराज्य को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच प्रतिद्वंद्विता सहित क्षेत्र की जटिल भू-राजनीतिक गतिशीलता से निपटने की आवश्यकता होगी।

अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा माहौल में बलपूर्वक यथास्थिति में होने वाले एकतरफा बदलावों के बीच कोरिया गणराज्य की रणनीतिक विदेश नीति में बदलाव आया है, खासकर मून जे-इन सरकार के चुने जाने के बाद से। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच संतुलन के निरंतर प्रयासों के रूप में सियोल की विदेश नीति की टाइपकास्टिंग को ध्यान में रखते हुए, यह जांचना प्रासंगिक था कि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा कारकों ने अंततः उनके विदेश नीति दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित किया है।

कोरिया गणराज्य की विदेश नीति दृष्टिकोण में विकास के इस अध्ययन ने संबंधित मुद्दों को संबोधित किया कि कैसे एक संप्रभु राष्ट्र-राज्य अपनी विदेश नीति निर्णय लेने में समायोजनात्मक परिवर्तन करता है। कोरिया गणराज्य के मामले का विश्लेषण करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि विदेशी नीतियों पर इसकी निर्णय लेने की प्रक्रिया अक्सर इसकी नीतिगत स्वायत्तता में बाधा डालने वाले क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभावों के कारण रणनीतिक द्विपक्षीयता से ग्रस्त रही है। इसके अलावा, अब यह स्पष्ट है कि कोरिया गणराज्य ने कोरियाई प्रायद्वीप से परे देखना शुरू कर दिया है और इंडोपैसिफ़िक जियोस्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में "वैश्विक निर्णायक राज्य" की भूमिका निभाने की धारणा को अपनाया है। इसलिए, इंडो-पैसिफ़िक के भीतर कोरिया गणराज्य की संभावित भूमिका की पहचान करना, विशेष रूप से भू-राजनीतिक बदलावों की अंतर्धाराएं अंतरराष्ट्रीय नियम-आधारित व्यवस्था में बाधा डालती हैं, जो सियोल की उभरती विदेश नीति में विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए व्यापक प्रेरणा प्रदान करती है।

इसके अलावा, अब यह स्पष्ट है कि कोरिया गणराज्य ने कोरियाई प्रायद्वीप से परे देखना शुरू कर दिया है और इंडोपैसिफ़िक जियोस्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में "वैश्विक निर्णायक राज्य" की भूमिका निभाने की धारणा को अपना लिया है।

अध्ययन यह समझने में भी मदद करता है कि कोरिया गणराज्य ने वर्षों से अपनी विदेश नीति के दृष्टिकोण में भारत जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ियों को कैसे देखा है। 2023 में भारत और कोरिया गणराज्य अपनी विशेष रणनीतिक साझेदारी के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, यह अध्ययन कोरिया गणराज्य के क्षेत्रीय दृष्टिकोण और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की पहचान करता है, जिन्हें अब एक नई सक्रिय इंडो-पैसिफ़िक रणनीति के माध्यम से ठीक किया जा रहा है। यह शोध अभिसरण और संभावित अवसरों के क्षेत्रों पर सिफारिशें भी प्रदान करता है जो अधिक गतिशील वैश्विक भूमिका प्राप्त करने में भारत-कोरिया गणराज्य संबंधों को संरेखित करेगा। अध्ययन उन प्रस्तावों में बदलावों को सामने लाता है, जिन्हें कोरिया गणराज्य ने अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने के लिए अपनाया है, धीरे-धीरे एक ऐसे दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है जो अब रणनीतिक रूप से अस्पष्ट नहीं बल्कि अग्रसक्रिय है।

लेखक के बारे में

डॉ. टुन्चिनमांग लैंगेल, इंडियन काउंसिल ऑफ़ वर्ल्ड अफ़ेयर्स (आईसीडब्ल्यूए) में रिसर्च फेलो हैं। उन्होंने स्कूल ऑफ़ इंटरनेशनल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से इंडो-पैसिफ़िक स्टडीज में पीएचडी की। उनकी पीएचडी इंडो-पैसिफ़िक में जापान और भारत के मिलते-जुलते सुरक्षा हितों पर है। आईसीडब्ल्यूए में शामिल होने से पहले, उन्होंने प्रतिष्ठित थिंक टैंक और नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन (एनएमएफ), फाउंडेशन फ़ॉर नेशनल सिक्योरिटी रिसर्च (एफएनएसआर) और कॉन्फेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) जैसे संगठनों के साथ काम किया है। उनके विभिन्न प्रकाशन प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें सहकर्मी-समीक्षित जर्नल लेख, पुस्तक अध्याय, वेब प्रकाशन आदि शामिल हैं। उनका नवीनतम सहकर्मी-समीक्षा प्रकाशन जर्नल ऑफ़ द इंडियन ओशन रीजन, एक टेलर एंड फ्रांसिस जर्नल में है। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शोधपत्र प्रस्तुत किये हैं। उनकी शोध रुचि का वर्तमान क्षेत्र इंडो-पैसिफ़िक के भीतर पूर्वोत्तर एशियाई देशों की भू-राजनीति पर केंद्रित है।

भारतीय
वैश्विक परिषद्

सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली 110 001, भारत

टेली : +91-11-2331 7246-49,फ़ैक्स: +91-11-2332 2710

www.icwa.in